Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 10
अंक : 239
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
शुक्रवार, 05 सितम्बर, 2025

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 महाराष्ट्र में छिड़ा 'मराठा बनाम ओबीसी' का ...

4 नेताओं को सुधारने के लिए बन रहे हैं ...

7 पैट कमिंस चोट के चलते भारत खिलाफ...

संक्षिप्त न्यूज

ई-रिक्शा के लिए भी भारत-एनकैप जैसा सुरक्षा मानक लाने पर विचारः गडकरी

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार देश में सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए ई-रिक्शा के लिए भी 'भारत एनकैप' की तर्ज पर सुरक्षा मानक लाने पर विचार कर रही है।

गडकरी ने फिक्की सड़क सुरक्षा पुरस्कार एवं संगोष्ठी के सातवें संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार के लिए एक अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा, देश में हर साल करीब पांच लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें 1.8 लाख लोगों की जान जाती है। इनमें से 66.4 प्रतिशत मौतें 18 से 45 वर्ष की उम्र वाले लोगों की होती हैं।

उन्होंने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने और घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पर बल दिया।

गडकरी ने इस प्रयास में ई-रिक्शा को सुरक्षित बनाने को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, "ई-रिक्शा की संख्या देश में बहुत अधिक है। हम देख रहे हैं कि किस तरह इनके लिए सुरक्षा मानकों में सुधार किया जा सकता है। हम ई-रिक्शा के लिए भी भारत-एनकैप जैसे सुरक्षा मानक लाने जा रहे हैं।"

उन्होंने चार-पहिया वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों को बेहतर करने के इरादे से वर्ष 2023 में भारत-एनकैप सुरक्षा मानक की शुरुआत की थी।

उन्होंने सड़क हादसों का जिक्र करते हुए कहा कि हेलमेट न पहनने से करीब 30,000 और सीट बेल्ट न लगाने से 16,000 मौतें होती हैं। सड़क हादसों से देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब तीन प्रतिशत नुकसान हो जाता है।

आजादी के बाद सबसे बड़ा फैसला!

मोदी बोले- जीएसटी सुधार दिवाली से पहले 'डबल धमाका'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा अनुमोदित व्यापक सुधारों की सराहना की और इन्हें भारत की आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा फ़ैसला बताया। दिल्ली के 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों से बातचीत करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी अब सरल हो गया है और दिवाली से पहले इन सुधारों को 'डबल धमाका' बताया। उन्होंने कहा कि अब जीएसटी और भी सरल हो गया है... 22 सितंबर को, जो कि नवरात्रि का पहला दिन है, अगली पीढ़ी का सुधार लागू हो जाएगा क्योंकि ये सभी चीजें निश्चित रूप से 'मातृशक्ति' से जुड़ी हैं।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी आज़ाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। दरअसल, ये सुधार देश के लिए समर्थन और विकास का दोहरा लाभ हैं। एक तरफ़ देश के आम लोगों का पैसा बचेगा, तो दूसरी तरफ़ देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी। उन्होंने कहा कि आठ साल पहले जब जीएसटी लागू हुआ था, तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था। यह चर्चा मोदी के

प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू नहीं हुई। ये चर्चाएँ पहले भी होती थीं, लेकिन कभी कोई काम नहीं हुआ।

मोदी ने कहा कि कोई नहीं भूल सकता कि कांग्रेस सरकार ने आपका मासिक बजट कैसे बढ़ा दिया था... वे बच्चों की टॉफियों पर भी 21इ टैक्स लगाते थे। अगर मोदी ने ऐसा किया होता, तो वे मेरे बाल नोच लेते। उन्होंने कहा कि जीएसटी में किए गए सुधारों का सारांश यह है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में पाँच रत्न जोड़ देगा। पहला, कर प्रणाली सरल हो जाएगी। भारत के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा, उपभोग और विकास दर में वृद्धि होगी, व्यापार करने में आसानी होगी, निवेश और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा, और एक विकसित भारत के लिए सहकारी संघवाद मज़बूत होगा।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं के लिए एक और लाभ फिटनेस सेक्टर में होने वाला है। जिम, सैलून, योग जैसी सेवाओं पर टैक्स कम कर दिया गया है, यानी हमारे युवा फिट भी रहेंगे और हिट भी। उन्होंने कहा कि लाल किले से मैंने वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाने का बड़ा आह्वान किया है। स्वदेशी यानि, जो कुछ भी हमारे देश में पैदा होता है, बनता है, जिसमें हमारे देश की मिट्टी की सुगंध है... वो मेरे लिए स्वदेशी है। इसलिए हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी का बोर्ड लगाकर हमें इस पर गर्व करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में ऐसी सरकार है जिसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति है जिसके दिल में उज्ज्वल भविष्य की चिंता है और बच्चों के भविष्य की चिंता है। ऐसे में हम किसी भी दबाव का परवाह किए बिना ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में कानून लाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के आज के विद्यार्थियों और आने वाली पीढ़ियों में एक सवाल शुरू से ही प्रचारित और प्रसारित किए जाने की जरूरत है। और वो सवाल है- मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे देश की किसी ना किसी आवश्यकता की पूर्ति हो।

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा एक्टिव

सभी सांसदों को 6 सितंबर तक दिल्ली पहुंचने का निर्देश

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सभी सांसदों को एक पत्र जारी कर 6 सितंबर तक दिल्ली पहुँचने का निर्देश दिया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी पार्टी सांसदों को 6 सितंबर को शाम 7 बजे अपने आवास पर रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया है। 7 सितंबर को सांसदों को सुबह 9 बजे से देर शाम तक आयोजित पार्टी कार्यशाला में शामिल होने का निर्देश दिया गया है।

यह कार्यशाला 8 सितंबर को संसद परिसर स्थित जीएमसी बालयोगी सभागार में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। उसी शाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सभी सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन करेंगे। 9 सितंबर को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंच तैयार है, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी से होगा।

विपक्ष को सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति पद के लिए मनाने की सरकार की कोशिशें नाकाम हो गई हैं, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें 'भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों' में से एक बताया गया है।

सोनिया गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत, जांच की मांग

नई दिल्ली। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नागरिकता प्राप्त करने से पहले भारतीय मतदाता का दर्जा प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेज़ बनाए। वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर की गई इस शिकायत में इस बात की जाँच की माँग की गई है कि अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनने से पहले ही सोनिया गांधी अपना वोट कैसे डाल पाईं।

यह मामला अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के समक्ष आया, जिन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष की विस्तृत दलीलें सुनीं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को तय की है। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सोनी और पवन नारंग शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए। अधिवक्ता नारंग ने तर्क दिया कि यह मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि कथित कृत्य एक 'संज्ञेय अपराध' है जिसकी पुलिस जाँच ज़रूरी है।

शिकायत के अनुसार, मूल रूप से इतालवी नागरिक सोनिया गांधी 30 अप्रैल, 1983 को नागरिकता अधिनियम की धारा 5 के तहत भारतीय नागरिक बन गईं।

नीतीश का बड़ा ऐलानः 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी नौकरी, बिहार में विकास की लहर

पटना। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आज सारण जिला के मढ़ौरा अनुमंडल अंतर्गत मढ़ौरा थाना के पीछे स्थित खेल मैदान में कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुझे प्रगति यात्रा की योजनाओं के स्थल भ्रमण एवं कार्यारम्भ एवं शिलान्यास के लिए यहाँ आने तथा आपसे बातचीत करने का मौका मिला है। यह बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यकर्ता संवाद में बड़ी संख्या में आप सब लोग उपस्थित हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप सब जानते हैं कि 2005 से पहले की सरकार ने बिहार के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, पहले बहुत बुरा हाल था। जब बिहार में 24 नवंबर, 2005 को एन0डी0ए0 की सरकार बनी, तब से हमलोग बिहार के विकास में लगे हुये हैं और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। शुरू से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया है। सात निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। हमलोगों ने सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, हर घर तक बिजली, हर घर तक पक्की गली एवं नाली का निर्माण आदि का काम कराया।

वर्ष 2020 में युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया। वर्तमान तक युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी एवं 39 लाख रोजगार दे दिया गया है। चुनाव से पहले ही 50 लाख से अधिक लोगों को नौकरी एवं रोजगार दे दिया जायेगा। हमलोगों ने अब तय किया है कि अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी / रोजगार दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2005-06 में नयी सरकार बनने के समय राज्य का बजट पहले से ही मात्र 28 हजार करोड़ रुपये था जिसे वर्ष 2006-07 में बढ़ाकर 34 हजार करोड़ रुपये किया गया और यह लगातार बढ़ते-बढ़ते अब 3 लाख 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में कुछ नये निर्णय लिये गये हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को प्रतिमाह मिलनेवाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। इससे 1 करोड़ 12 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। वर्ष 2005 से पहले बिहार में बिजली आपूर्ति की स्थिति काफी दयनीय थी.

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में एफआरए 'उल्लंघन' पर राहुल चिंतित, जनजातीय मामलों के मंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम को पत्र लिखकर ग्रेट निकोबार परियोजना को दी गई मंजूरी में वन अधिकार अधिनियम के कथित उल्लंघन पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि इस परियोजना को लेकर जनजातीय परिषद और स्थानीय समुदायों द्वारा उठाई गई चिंताओं की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी विकास योजना न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के सम्मान के सांविधानिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए।

राहुल गांधी का आरोप- दबाव में ली गई एनओसी

राहुल गांधी ने लिखा, 'ग्रेट निकोबार परियोजना को मंजूरी देने में वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार की जनजातीय परिषद ने बताया है कि निकोबारी और शोम्पेन समेत जनजातीय समुदायों से अधिनियम के तहत ठीक से सलाह-मशविरा नहीं किया गया।'

उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पूरी जानकारी दिए दबाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) ली गई और बाद में जब असली जानकारी सामने आई तो परिषद ने उसे वापस ले लिया।

आदिवासी समुदाय को ये सता रहा डर

गांधी ने तीन सितंबर को लिखे अपने पत्र में कहा कि आदिवासी समुदाय 2004 की सुनामी के दौरान विस्थापित हो गए थे और अपनी पैतृक भूमि पर वापस नहीं लौट पाए। अब उन्हें डर है कि यह परियोजना उनकी जीवनशैली और अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन जाएगी। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि जनजातीय परिषद और स्थानीय समुदायों की चिंताओं को गंभीरता से देखें और वन अधिकार अधिनियम का सही मायने में पालन सुनिश्चित करें।

जयराम रमेश भी परियोजना का लगातार कर रहे विरोध

कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश भी इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह पारिस्थितिकी और क्षेत्र के वनवासियों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए हानिकारक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसे जबरन आगे बढ़ा रही है।

पिछले हफ्ते कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर निकोबारी जनजाति के सांविधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा की मांग की थी। टैगोर ने कहा था कि प्रशासन ने गलत दावा किया कि FRA के तहत अधिकार तय हो चुके हैं और इसी आधार पर 13,075 हेक्टेयर जंगल की जमीन को परियोजना के लिए साफ कर दिया गया। लेकिन जनजातीय परिषद ने इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि इस प्रक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा करवाई जाए, FRA के अधिकार पूरी तरह मान्य किए जाएं, जब तक कानून का पालन न हो प्रोजेक्ट रोका जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

'बिना पूर्व भुगतान के दुर्घटना पीड़ितों का तुरंत इलाज करें, वरना लगेगा जुर्माना', अस्पतालों को आदेश

बंगलूरू। कर्नाटक सरकार ने सभी चिकित्सा संस्थानों और डॉक्टरों को याद दिलाया कि वे किसी भी दुर्घटना पीड़ित का तुरंत उपचार करें और उनसे किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान (एडवांस पेमेंट) न मांगें।

एक सरकारी आदेश में बुधवार को यह निर्देश दिया गया।

सरकार ने कहा, यह जरूरी है कि कानून और राज्य में चल रही योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियों और आम लोगों को एक बार फिर बताया जाए कि दुर्घटना पीड़ितों का इलाज बिना देरी और बिना एडवांस पेमेंट के किया जाना अनिवार्य है। कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अधिनियम, 2007 के तहत, दुर्घटना पीड़ित की परिभाषा केवल सड़क हादसों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जलने, जहर खाने या आपराधिक हमलों जैसी स्थितियां भी शामिल हैं।

'नियम के उल्लंघन पर अस्पताल को लगेगा एक लाख का जुर्माना'

आदेश में कहा गया, जब भी कोई

ऐसा दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में आता है या लाया जाता है, तो उसका आपात स्थिति में तत्काल उपचार किया जाना चाहिए अग्रिम भुगतान की मांग नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई अस्पताल इस नियम का उल्लंघन करता है, तो धारा 19 (5) के तहत उस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

'कानून के अनुसार आवश्यक उपचार प्रदान करना जरूरी'

सरकार ने कर्नाटक गुड समेरिटन एंड मेडिकल प्रोफेशनल एक्ट, 2016 का भी हवाला देते हुए कहा कि हर अस्पताल को मुफ्त मेडिकल स्क्रीनिंग, फर्स्ट-एड और आवश्यक उपचार प्रदान करना अनिवार्य है, ताकि मरीज की स्थिति में सुधार हो सके। अगर किसी अस्पताल में इलाज की सुविधाएं नहीं हैं, तो उसे पहले मरीज को स्थिर करना होगा और फिर दूसरी जगह रेफर करना होगा, साथ ही चिकित्सा दस्तावेज भी देना होगा। इसके अलावा, सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 187 का भी हवाला देते हुए कहा कि नियमों का पालन न करने पर तीन महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना और दोबारा अपराध करने पर छह महीने की जेल या 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।

जीएसटी दरों में कटौती देश के लिए बड़ी सौगात, दिल्ली को फायदा होगा : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती देश के लिए एक बड़ा उपहार है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

बुधवार को जीएसटी परिषद की पहली बैठक में शामिल हुईं गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस कदम से देश में व्यापार और कारोबार मजबूत होगा।

रेखा गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा, "यह देश के लिए बहुत बड़ी सौगात है... स्वास्थ्य बीमा और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दरों में कटौती देश के करोड़ों लोगों के लिए बड़ी राहत है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आभारी हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी की दरों में संशोधन को अपार समर्थन के साथ पारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा तथा यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा।

गुप्ता ने कहा, " दिल्ली बहुत खुश है और मैं दिल्लीवासियों की ओर से प्रधानमंत्री को स्वास्थ्य बीमा तथा शिक्षा संबंधी वस्तुओं पर शून्य जीएसटी लगाने के लिए धन्यवाद देती हूं। नवीकरणीय ऊर्जा को समर्थन दिया गया है और इससे दिल्ली को काफी लाभ होगा क्योंकि हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं।"

जीएसटी परिषद ने बुधवार को आम सहमति से माल एवं सेवा कर में व्यापक सुधारों को मंजूरी दी।

ममता बनर्जी का भाजपा पर वारः

बंगाल में एक भी विधायक नहीं बचेगा, हार तय है

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि वह बांग्ला भाषी लोगों के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को एक ऐसे समय का सामना करना पड़ेगा जब पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी का एक भी विधायक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बंगालियों के खिलाफ भाषाई आतंक फैलाने वाली कोई भी पार्टी बंगाल कभी नहीं जीत सकती।

ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगालियों पर हो रहे अत्याचार के लिए भाजपा की निंदा करती हूँ। जल्द ही एक समय आएगा जब बंगाल में भाजपा का एक भी विधायक नहीं बचेगा। जनता खुद यह सुनिश्चित करेगी। भाजपा की हार निश्चित है, क्योंकि बंगालियों के खिलाफ भाषाई आतंक फैलाने वाली कोई भी पार्टी बंगाल कभी नहीं जीत सकती। ममता बनर्जी ने भाजपा को 'वोट चोर' पार्टी बताते हुए कहा कि

यह पूरी तरह से भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट चोर, पूरी तरह से भ्रष्ट, बंगालियों को सताने वाली और धोखेबाज़ पार्टी है। भाजपा राष्ट्रीय कलंक है और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ।

तृणमूल कांग्रेस ने नियम 169 के तहत देश भर में बंगाली भाषी लोगों के खिलाफ कथित घटनाओं की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। ममता बनर्जी के बोलने के दौरान उन्हें विपक्ष के भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल को निलंबित कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पूर्व अनुमति और सुरक्षा जमा के बावजूद अपने 'भाषा आंदोलन विरोध स्थल' को ध्वस्त करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि 'मेयो रोड पर जो हुआ वह सेना का काम नहीं है'।

ओवैसी का केंद्र पर तीखा हमलाः

जीएसटी सुधार 'बयानबाजी', राज्यों को 10,000 करोड़ का नुकसान

हैदराबाद। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को केंद्र सरकार के इस दावे की आलोचना की कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में नवीनतम सुधारों से उपभोग बढ़ेगा और कहा कि पिछले एक दशक में इस तरह की बयानबाजी और संवाद से आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ है। एआईएमआईएम नेता ने चेतावनी दी कि इन बदलावों के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से 8,000-10,000 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है।

मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हमने जो भी बयानबाजी और संवाद देखे हैं, उनसे आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ है। हम इसका स्वागत नहीं कर सकते क्योंकि इसका राज्यों के राजस्व और वित्त पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और प्रत्येक राज्य को 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा। इस बीच, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने जीएसटी दरों को दो स्लैब में तर्कसंगत बनाने के केंद्र के फैसले में देरी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि वह 1 जुलाई, 2017 को इसे लागू करने के आठ साल बाद अपनी गलती का 'एहसास' करने के लिए सरकार की सराहना करते हैं।

उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन सहित कई अर्थशास्त्रियों ने कर ढांचे को लेकर चिंता जताई थी जब इसे पहली बार लागू किया गया था। मदुरै में पत्रकारों से बात करते हुए चिदंबरम ने कहा, 'मैं आठ साल बाद अपनी गलती का एहसास होने के लिए सरकार की सराहना करता हूँ।

महाराष्ट्र में अजब गजब सियासत!

संजय राउत ने की फडणवीस की तारीफ, शिंदे-पवार को घेरा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने मराठा आरक्षण आंदोलन को सुलझाने और कार्यकर्ता मनोज जारंगे की भूख हड़ताल समाप्त करने का श्रेय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया। संजय राउत द्वारा यह भाजपा नेता की एक दुर्लभ सराहना है। पत्रकारों से बात करते हुए, राउत ने कहा कि फडणवीस ने पर्दे के पीछे से काम किया और मराठा आरक्षण पर कैबिनेट उप-समिति के साथ विचार-विमर्श में शामिल रहे। राउत ने कहा कि अगर सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाया है और जरांगे की जान बचाई है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे को सुलझाने के लिए विचार-विमर्श में शामिल थे। वह पृष्ठभूमि में काम कर रहे थे। सारा श्रेय फडणवीस को जाना चाहिए। जारंगे और मराठा प्रदर्शनकारियों द्वारा मुख्यमंत्री की कड़ी आलोचना का जिक्र करते हुए राउत ने

कहा, 'मैं फडणवीस के धैर्य की भी सराहना करूंगा।' राउत भाजपा और फडणवीस के कटु आलोचक रहे हैं। हालाँकि, उन्होंने दावा किया कि जब जरांगे अपना अनशन शुरू करने मुंबई आए थे, तो भाजपा नेताओं ने अलग भाषा बोली थी। राउत ने दावा किया कि फडणवीस को छोड़कर भाजपा नेताओं ने 'अत्यधिक नफ़रत फैलाने' की कोशिश की।

शिवसेना (यूबीटी) ने मराठा आंदोलन को लेकर उप-मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। राउत ने कहा, 'एकनाथ शिंदे और अजित पवार कहाँ थे? उन्होंने विचार-विमर्श में भाग क्यों नहीं लिया? क्या वे चाहते थे कि मामला बिगड़े और फडणवीस मुश्किल में पड़ें।' वहीं, राउत ने महाराष्ट्र के हालिया मराठा आरक्षण निर्णय में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हुए कैबिनेट मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल से इस्तीफा देने का आग्रह किया है।

राउत ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देने के इरादे से मराठा आरक्षण आंदोलन की योजना बनाने का आरोप लगाया। अपने समुदाय के हितों की रक्षा की मांग करते हुए, भुजबल ने सरकार के रुख पर निराशा व्यक्त की। इस बीच, राज्य सरकार द्वारा मराठों को ओबीसी का दर्जा देने पर विचार करने की प्रतिबद्धता जताए जाने के बाद कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी, जिससे हाल के सरकारी प्रस्तावों के बाद कोटा कार्यान्वयन के माध्यम से संभावित लाभ का संकेत मिलता है।

गोवा कॉन्फ्रेंस में मुंबई पुलिस का डंका

गोवा अन्यूएल सिक्यूरिटी कांफ्रेन्स फॉर बेस्ट जोन एलएसएएस और एलईएएस के लिए वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन' सम्मेलन में मुंबई पुलिस सम्मानित

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई - मुंबई पुलिस और खासकर साइबर सेल ने मुंबईकरों के 21,033 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें वापस किया है। इस उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने गोवा अन्यूएल सिक्यूरिटी कांफ्रेन्स फॉर बेस्ट जोन एलएसएएस और एलईएएस के लिए वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन' सम्मेलन में पुलिस को यह सम्मान दिया है।

इस सम्मेलन का आयोजन दूरसंचार विभाग ने किया था। इस अवसर पर मुंबई पुलिस के विशेष पोर्टल को खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद करने में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया और मुंबई पुलिस के साइबर सेल के उपायुक्त पुरुषोत्तम कराड को एक विशेष प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

यह सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने किया था। इसमें मुंबई पुलिस के सीईआयआर (केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर) पोर्टल के माध्यम से कुल 21,033 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए और शिकायतकर्ताओं को वापस कर दिए

गए मुंबई पुलिस ने पुलिस उपायुक्त (साइबर अपराध) मुंबई को पोर्टल का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। दूरसंचार महानिदेशक सुनीता चंद्रा ने मुंबई पुलिस की ओर से उपस्थित पुलिस उपायुक्त (साइबर अपराध) पुरुषोत्तम कराड को प्रशंसा पत्र प्रदान किया। मुंबई पुलिस की इस सफलता में मुंबई पुलिस की पूरी टीम की अहम भूमिका रही है और यह उनके अथक प्रयासों का परिणाम है, ऐसा आभार व्यक्त किया गया।

यह काम मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, सह पुलिस आयुक्त (अपराध) लखमी गौतम, सह पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) शैलेश बलकवड़े, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मध्य प्रदेशिक विभाग) विक्रम देशमाने, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पूर्व प्रादेशिक विभाग) महेश पाटिल, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम प्रादेशिक विभाग) परमजीत सिंह दहिया, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (उत्तर प्रदेशिक विभाग) शशि कुमार मीणा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिण प्रादेशिक विभाग) डॉ. अभिनव देशमुख, पुलिस उपायुक्त (साइबर अपराध) पुरुषोत्तम कराड, सभी पुलिस स्टेशनों में इस पोर्टल के प्रभारी अधिकारियों और सीईआयआर नोडल अधिकारियों के मार्गदर्शन में सभी क्षेत्रों के पुलिस उपायुक्तों के साथ मिलकर किया गया है।

महाराष्ट्र में काम के घंटों में बड़ा बदलाव

निजी कर्मचारियों को अब 9 की बजाय 10 घंटे काम

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य अवधि को मौजूदा नौ घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के लिए कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी। आधिकारिक बयान के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कार्यबल द्वारा सुझाए गए बदलावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र अब कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों में शुमार हो गया है, जहां ऐसे सुधार पहले ही लागू किए जा चुके हैं।

बयान में बताया गया है कि ये संशोधन, फैक्टरी अधिनियम, 1948 और महाराष्ट्र दुकान एवं स्थापना (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 2017 में किए जाएंगे। संशोधनों के बाद उद्योगों को अधिक मांग या श्रमिकों की कमी के दौरान बिना व्यवधान काम करने की अनुमति होगी, वहीं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि श्रमिकों को ओवरटाइम का उचित मुआवज़ा मिले। इसके तहत उद्योगों में दैनिक कार्य घंटों की सीमा नौ से बढ़ाकर 12 घंटे की जाएगी। वहीं विश्राम का समय पांच घंटे की बजाय छह घंटे के बाद मिलेगा।

कानूनी ओवरटाइम की सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर प्रति तिमाही 144 घंटे की जाएगी और इसके लिए श्रमिकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। साप्ताहिक कार्य घंटे भी साढ़े दस घंटे से बढ़ाकर 12 कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार, संशोधित दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत दैनिक कार्य घंटों को नौ से बढ़ाकर 10 घंटे, ओवरटाइम की सीमा 125 से बढ़ाकर 144 घंटे और आपातकालीन ड्यूटी घंटों को 12 घंटे कर दिया जाएगा। यह बदलाव 20 या उससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे। बीस से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को अब पंजीयन प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उन्हें केवल सूचना प्रक्रिया के तहत अधिकारियों को अवगत कराना होगा।

सरकार के अनुसार, यह कदम कारोबार में सुगमता लाएगा, नए निवेश आकर्षित करेगा, रोज़गार को बढ़ावा देगा और साथ ही श्रमिकों के वेतन संरक्षण एवं अधिकारों में सुधार सुनिश्चित करेगा। इसमें ओवरटाइम पर दोगुना वेतन देना भी शामिल है। श्रम विभाग ने पिछले सप्ताह यह प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष पेश किया था। विभाग का कहना है कि प्रस्तावित बदलाव, खासकर महिलाओं के लिए, अधिक आरामदायक कार्य वातावरण उपलब्ध कराएंगे और कर्मचारियों व नियोक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान करेंगे।

सात ट्रेनों का विभिन्न स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए सात ट्रेनों का विभिन्न स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1.03 सितंबर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 12216 बांद्रा टर्मिनस-दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट गरीब रथ एक्सप्रेस महेसाणा स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन 20:42 बजे महेसाणा स्टेशन पहुँचेगी और 20:44 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार, 04 सितंबर, 2025 को दिल्ली सराय रोहिल्ला से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 12215 दिल्ली सराय रोहिल्ला-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट गरीब रथ एक्सप्रेस महेसाणा स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन 22:05 बजे महेसाणा स्टेशन पहुँचेगी और 22:07 बजे प्रस्थान करेगी।

2.08 सितंबर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22915 बांद्रा टर्मिनस-हिसार सुपरफास्ट एक्सप्रेस (साप्ताहिक) सिद्धपुर स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन सिद्धपुर स्टेशन पर 21:23 बजे पहुंचेगी और 21:25 बजे प्रस्थान करेगी।

3. 8 सितंबर, 2025 को गांधीधाम से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 20935 गांधीधाम-इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (साप्ताहिक) सामाख्याली स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन 19:10 बजे सामाख्याली स्टेशन पहुँचेगी और 19:12 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार, 7 सितंबर, 2025 को इंदौर से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 20936 इंदौर-गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस (साप्ताहिक) सामाख्याली स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन 12:40 बजे सामाख्याली स्टेशन पहुँचेगी और 12:42 बजे प्रस्थान करेगी।

4. 06 सितंबर, 2025 को इंदौर से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 14802 इंदौर-जोधपुर एक्सप्रेस गौतमपुरा रोड स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन गौतमपुरा रोड स्टेशन पर 05:17 बजे पहुँचेगी और 05:19 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार, 05 सितंबर, 2025 को जोधपुर से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 14801 जोधपुर-इंदौर एक्सप्रेस गौतमपुरा रोड स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन गौतमपुरा रोड स्टेशन पर रात 21:50 बजे पहुँचेगी और 21:52 बजे प्रस्थान करेगी।

5.7 सितंबर, 2025 को बेंगलुरु से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 16534 बेंगलुरु-भगत की कोठी एक्सप्रेस (साप्ताहिक) महेसाणा स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन महेसाणा स्टेशन पर 06:50 बजे पहुँचेगी और 06:52 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार, 10 सितंबर, 2025 को भगत की कोठी से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 16533 भगत की कोठी-बेंगलुरु एक्सप्रेस (साप्ताहिक) महेसाणा स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन महेसाणा स्टेशन पर 12:22 बजे पहुँचेगी और 12:24 बजे प्रस्थान करेगी।

6. 06 सितंबर, 2025 को तिरुवनंतपुरम से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 16312 तिरुवनंतपुरम-श्री गंगानगर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) महेसाणा स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन महेसाणा स्टेशन पर 08:38 बजे पहुँचेगी और 08:40 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार, 09 सितंबर, 2025 को श्री गंगानगर से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 16311 श्री गंगानगर-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस (साप्ताहिक) महेसाणा स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन महेसाणा स्टेशन पर 05:45 बजे पहुँचेगी और 05:47 बजे प्रस्थान करेगी।

7. 04 सितंबर, 2025 को बरेली से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 14311 बरेली-भुज आला हजरत एक्सप्रेस (त्रि-साप्ताहिक) मालिया मियाना स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन मालिया मियाना स्टेशन पर 06:43 बजे पहुंचेगी और 06:45 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मेल-एक्सप्रेस ट्रेन चोरी में शामिल गिरोह पर्दाफाश 2 आरोपी गिरफ्तार, 23 लाख रुपये के आभूषण और नकदी जब्त

मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार

रेलवे पुलिस आयुक्त राकेश कलासागर के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और सायबर को पुलिस को मिली बड़ी सफलता

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई :रेलवे पुलिस ने लंबी दूरी की ट्रेनों से यात्रियों का कीमती सामान लूटने और लाखों की लूट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। उनके पास से 22 लाख 24 हजार 769 रुपये के सोने के आभूषण और नकदी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम वकार आलम तोकीर खान और जुगल किशोर ओमप्रकाश विश्वकर्मा हैं। वहीं पुलिस उनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। 13 मई से 24 मई के बीच, जब यात्री और शिकायतकर्ता कोयंबटूर राजकोट एक्सप्रेस के कोच में सो रहे थे, आरोपियों ने एक धारदार हथियार से उनकी पैंट की जेबें काट दीं और 3.5 लाख रुपये की चार सोने की चूड़ियाँ, एक चांदी का लॉकेट और 3.6 लाख रुपये की नकदी चुरा ली। शिकायतकर्ता की शिकायत पर कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

इस बीच, पुलिस ने देखा था कि रात में

मुंबई आने और जाने वाली मेल-एक्सप्रेस में बैग और पर्स की चोरी के कई अपराधों की कार्यप्रणाली एक जैसी थी। तदनुसार, पुलिस ने एक जांच शुरू की थी। इससे, रेलवे पुलिस की कल्याण यूनिट -3 (अपराध शाखा) के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपराध की कार्य पद्धति और समय का अध्ययन कर रहे थे और ऐसे अपराध करने वाले आरोपियों की तलाश कर रहे थे। इस बीच, 25 अगस्त को विशेष मुखबिर के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर पता चला कि आरोपी कल्याण स्टेशन के पास आने वाला है तदनुसार, आरोपी वकार आलम तोकीर खान और जुगल किशोर ओमप्रकाश विश्वकर्मा (उत्तर प्रदेश के निवासी) को कल्याण रेलवे स्टेशन के पश्चिम में शहर की सीमा से गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ में पता चला कि उन्होंने अपने 4 अन्य साथियों के साथ इस पंजीकृत अपराध के अलावा कई अन्य चोरी के अपराधों को अंजाम दिया है। तदनुसार, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कल्याण, कर्जत, डोंबिवली और ठाणे रेलवे पुलिस स्टेशनों में दर्ज 16 अपराधों को हल किया है। यह कार्रवाई रेलवे पुलिस आयुक्त राकेश कलासागर, मध्य परिमंडल उपायुक्त प्रज्ञा जेडगे, सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेंद्र राणमाले के मार्गदर्शन में, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय खेडकर और पुलिस निरीक्षक रोहित सावंत (अपराध शाखा) के नेतृत्व में तथा साइबर सेल अधिकारी मंगेश खाडे और देवीदास अरण्ये के तकनीकी सहयोग से किया गया है।

देश भर में 75 स्थानों पर नमो मैराथन का आयोजन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस पहल के तहत, युवाओं में खेल के प्रति प्रेम जगाने और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश फैलाने के लिए देश भर में 75 स्थानों पर नमो मैराथन का आयोजन किया जाएगा, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी।

इस संबंध में, डॉ. मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के खेल मंत्रियों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले एवं खेल सचिव हरिरंजन राव उपस्थित थे। राज्य के खेल मंत्री एडवोकेट माणिकराव कोकाटे और विभिन्न राज्यों के खेल मंत्री भी उपस्थित थे।

मंत्री डॉ. मंडाविया ने कहा कि युवाओं को स्वस्थ रखना और उनमें देशभक्ति की भावना जगाना समय की मांग है। इसलिए, प्रत्येक राज्य को इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और इन्हें सफल बनाना चाहिए।

इस पखवाड़े में 21 सितंबर को 75 स्थानों पर नमो मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद, सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे देश में एकता का संदेश देने वाली पदयात्रा निकाली जाएगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में एकता, देशभक्ति, एक भारत, श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत का संदेश देने वाली तीन दिवसीय पदयात्रा आयोजित की जाएगी।

इस दौरान, नशामुक्त भारत अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान देश भर के 100 सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों की भागीदारी से चलाया जाएगा। साथ ही, संसद खेल महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने राज्यों से इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की।

पश्चिम रेलवे

पिट लाइनों का विस्तार

वरिष्ठ डीईएन (दक्षिण) मुंबई सेंट्रल ई-निविदा सूचना संख्याः बीसीटी/25-26/197 दिनांक 01.09.2025 आमंत्रित करता है। **कार्य और स्थानः** मुंबई सेंट्रल (सीएफओ यार्ड) पिट लाइन संख्या 5 और 6 का विस्तार, कवरशेड (60 मीटर तक) और संबद्ध सुविधाओं सहित। **कार्य की अनुमानित लागतः** 96,29,064.97। **ब्याज राशिः** 1,92,600/-। **जमा करने की तिथि और समयः** 26.09.2025, 15:00 बजे तक। **खोलने की तिथि और समयः** 26.09.2025 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएँ। 0559

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

मध्य रेल

ओएचई कार्य

खुली निविदा सूचना स. BB.LD.585. W.881.CONTR2, दिनांक:01.09.2025. कार्य का नाम: सीएसएमटी-कल्याण उपनगरीय मार्ग पर 15 कार ईएमयू सेवाओं के संचालन के संबंध में, मुंबई मंडल के मुंब्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 में 25 केवी एसी ओएचई संशोधन कार्य। **अनुमानित लागत:** रु. 79,26,763.39. **बिड सिक्योरिटी:** रु. 1,58,500/-. **ऑफर की वैधता:** 60 दिन। **समापन अवधि:** 12 महीने। **निविदा फार्म का मूल्य:** रु. 0/- . **I) उक्त निविदा का निविदा बंद करने की तारीख और समय: दिनांक 24.09.2025 को 11:00 बजे तक, और 11:00 बजे के बाद खोला जाएगा। II)** शुद्धिपत्रक के विवरण हेतु अग्रदर्शी निविदाओं के लिए वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर भेट देने का अनुरोध है। **III)** केवल वेबसाइट **www.ireps.gov.in** के माध्यम से उपर्युक्त इलेक्टॉनिकलि ई-टेन्डर में निविदाधारक सहभाग ले सकते है और ई-टेन्डर के अलावा हस्तचलित प्रस्तुत करने का निवेदन देने की अनुमति नही है। हस्तचलित रूप से, यदि निविदा खुलने के बाद की प्रस्तुति का विचार नही किया जाएगा। **IV)** निविदा दस्तावेज में दिए गए विवरण के अनुसार बिड सिक्योरिटी का भुगतान किया जाना चाहिए। **V)** अतिरिक्त जानकारी के लिए संपर्क: वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (कर्षण वितरण), दूसरी मंजील, एनेक्स भवन, सीएसएमटी मुंबई - 400001. फोन-022-22612355. निवीदाओं संबंधी संपूर्ण विवरण वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदा संबंधी संपूर्ण विवरण वरिष्ठ मंडल विदुयत अभियंता (कर्षण (वितरण), दूसरी मंजील, एनेक्स भवन, सीएसएम टी मुंबई - 400001 के "नोटिस बोर्ड" पर भी उपलब्ध है। **DE-422**

खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

पश्चिम रेलवे के सांताक्रुज एवं गोरेगाँव स्टेशनों के बीच रविवार को जम्बो ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे द्वारा ट्रैक, सिगनलिंग तथा ओवर हेड उपस्करों के रख-रखाव हेतु रविवार, 07 सितम्बर, 2025 को सांताक्रुज एवं गोरेगाँव स्टेशनों के बीच 10.00 बजे से 15.00 बजे तक अप तथा डाउन फ़ास्ट लाइनों पर पाँच घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जायेगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस ब्लॉक अवधि के दौरान सभी फास्ट लाइन की उपनगरीय ट्रेनों को गोरेगांव एवं सांताक्रुज स्टेशनों के बीच धीमी लाइन पर चलाया जायेगा।

ब्लॉक के दौरान कुछ उपनगरीय ट्रेनें निरस्त रहेंगी और कुछ अंधेरी एवं बोरीवली ट्रेनों को गोरेगाँव तक हार्बर लाइन पर चलाया जाएगा।

इस सम्बंध में विस्तृत जानकारी सभी स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है।

पश्चिम रेलवे बांद्रा ⇄ टर्मिनस भगत की कोठी के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाएगा

ट्रेन संख्या	प्रारंभिक स्टेशन और गंतव्य	सेवा की तिथियां	प्रस्थान	आगमन
04828	बांद्रा टर्मिनस - भगत की कोठी	28.09.2025 to 28.12.2025	10:30 hrs (रविवार)	04:30 hrs (अगले दिन)
04827	भगत की कोठी- बांद्रा टर्मिनस	27.09.2025 to 27.12.2025	11:30 hrs (शनिवार)	07:25 hrs (अगले दिन)

ठहरावः बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, साबरमती, महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, जवाई बांध, फालना, रानी, मारवाड़, पाली मारवाड़ और लूणी स्टेशन दोनों दिशाओं में।

संयोजनः एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी 3-टियर (इकोनॉमी), शयनयान और सामान्य द्वितीय श्रेणी डिब्बे।

समय, ठहराव और संयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं।

ट्रेन संख्या 04828 की बुकिंग 06.09.2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। उपरोक्त ट्रेन विशेष किराए पर विशेष ट्रेन के रूप में चलेगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
Like us on: facebook.com/WesternRly
Follow us on: X.com/WesternRly
Follow us on: Instagram/WesternRly

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ लाएँ

मध्य रेल

सोलापुर मंडल

TRANSPORTATION OF P.WAY MATERIALS & FITTINGS

मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) सोलापुर, भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी और से निम्नलिखित कार्यों के लिये ई-निविदाये आमंत्रित करते है। **निविदा क्र: 24-2025-SrDENS, दिनांक 03.09.2025. कार्य का नाम:** Transportation of P.Way materials & fittings from other division, transportation of various types of sleepers from sleeper factories to Solapur division and within Solapur division under SSE/P.Way/Store Solapur for two years. **अनुमानित लागत:** रु.6,35,77,263.81. **बयाना रक्कम:** रु.4,67,900/-. **समापन की अवधी:** 24 Months. **अनुरक्षण की अवधी:** NA. **www.ireps.gov.in इस वेब साईट पर टेंडर अपलोड करने कि अंतिम दिनांक और समय: 25.09.2025 को 15.00 बजे तक। www.ireps.gov.in इस वेब साईट पर टेंडर खुलने का दिनांक और समय: 25.09.2025 को 15.30 बजे।** निविदाकारोंसे निवेदन है की कोई बदलाव / शुद्धिपत्र (यदि हो) के लिये Website: **www.ireps.gov.in** पर टेंडर बंद होने की तारीख तक समय समय पर भेंट दे।

मंडल रेल प्रबंधक (कार्य), मध्य रेल, सोलापुर

DE/Sur-61

खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

महाराष्ट्र में छिड़ा 'मराठा बनाम ओबीसी' का नया विवाद, आरक्षण को लेकर आखिर क्यों खिच गई हैं तलवारें

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर नया टकराव सामने आ गया है। सरकार ने मराठा आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे की 8 में से 6 मांगें मान लीं और मराठाओं को मराठा-कुणबी जाति प्रमाणपत्र देने का निर्णय लिया। इससे मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। जरांगे ने कहा कि अब मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के मराठा समुदाय को आरक्षण मिलेगा।

ओबीसी नेता भुजबल कैबिनेट बैठक से रहे नदारद

सरकार के फैसले से मराठा समुदाय में संतोष है, जबकि ओबीसी समाज में नाराजगी दिख रही है। ओबीसी नेता और मंत्री छगन भुजबल कैबिनेट बैठक से अनुपस्थित रहे और दोहराया कि यदि मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल किया तो बड़ा आंदोलन होगा। ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके ने चेतावनी दी कि सरकार के पास मराठाओं को कुणबी प्रमाणपत्र देने का अधिकार नहीं है और ओबीसी समुदाय

सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगा।

मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच, महाराष्ट्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक कैबिनेट उपसमिति का गठन किया है। सूत्रों के अनुसार, यह उपसमिति ओबीसी आबादी के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं पर काम करेगी। वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले को उपसमिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

मराठा आरक्षण विवाद

महाराष्ट्र सरकार द्वारा ओबीसी कल्याण पर एक कैबिनेट उपसमिति का गठन मराठा आरक्षण की मांगों को लेकर चल रहे तीव्र विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में हुआ है। यह कदम मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे द्वारा मुंबई में अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त करने के फैसले के ठीक बाद उठाया गया है। आज़ाद मैदान में पाँच दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मराठा नेता मनोज जरांगे ने राज्य द्वारा प्रमुख मांगों पर सहमति जताने के बाद प्रदर्शनकारियों की 'जीत' की घोषणा की। समर्थकों से घिरे जरांगे ने मंगलवार शाम वरिष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा दिए गए जूस को पीकर अपना अनशन समाप्त किया। सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र के पात्र मराठा परिवारों को ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने का आश्वासन दिया। जाति प्रमाण पत्र की घोषणा के अलावा, राज्य सरकार आरक्षण विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने पर भी सहमत हुई है। इससे पहले, प्रदर्शनकारियों ने ओबीसी श्रेणी के तहत नौकरियों और शिक्षा में 10इ आरक्षण की मांग की थी।

ग्राहकों की सुविधा के लिए सहकारी उपभोक्ता भंडारों के माध्यम से बिक्री के प्रयास-विपणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई। केंद्र सरकार की ओर से, नैफेड के माध्यम से 'भारत' ब्रांड के उत्पाद आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि राज्य में सहकारी उपभोक्ता भंडारों के सहयोग से 'भारत' आटा, चावल और प्याज, जो इसका हिस्सा हैं, आम जनता को उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएँगे।

आवश्यक और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की किफायती कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय 'भारत' ब्रांड के उत्पादों का विपणन कर रहा है। इसके तीसरे चरण का शुभारंभ विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने सह्याद्री अतिथि गृह में किया। इस अवसर पर नैफेड की ओर से राज्य प्रमुख भव्य आनंद उपस्थित थीं।

विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने इन मोबाइल वाहनों को बिक्री के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान, इन उत्पादों का वितरण ग्राहकों को प्रतिनिधि रूप से किया गया।

मंत्री रावल ने कहा कि राज्य में इस

समय त्योहारों का मौसम है। इस दौरान उपभोक्ताओं को कम दामों पर गुणवत्तापूर्ण आटा, चावल और प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इन उत्पादों की बाजार कीमतों को और कम करने में मदद मिलेगी, जिससे मुद्रास्फीति भी कम होगी। नैफेड का नेटवर्क राज्य और देश भर में फैला हुआ है, जिसके माध्यम से ये उत्पाद सीधे किसानों से खरीदे जाते हैं, जिससे इन्हें कम दामों पर बेचना संभव हो रहा है और इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि यदि नैफेड साल भर की खरीद योजना तैयार करे और अन्य उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से बिक्री के लिए उपलब्ध कराए, तो उपभोक्ताओं को अधिक लाभ मिलेगा।

'भारत' ब्रांड की इस पहल के तहत, आज बिक्री के लिए आए 'भारत आटा' की कीमत बाजार मूल्य से कम 31.50 रुपये प्रति किलोग्राम और 'भारत चावल' की कीमत 34 रुपये प्रति किलोग्राम रखी गई है। प्याज बिक्री के लिए उपलब्ध है। उपभोक्ताओं की व्यापक पहुँच और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, इन उत्पादों का वितरण रिलायंस रिटेल, डी-मार्ट, विशाल मार्ट जैसी प्रमुख संगठित खुदरा श्रृंखलाओं और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर नेफेड की राज्य प्रमुख भव्या आनंद ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भारत ब्रांड के उत्पादों को सीधे घरों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन तैनात की गई हैं।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए उम्मीदवारों के पास दो महीने का समय- सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। राज्य में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने बताया कि इस संबंध में सरकार का निर्णय जारी कर दिया गया है। मंत्री श्री शिरसाट ने कहा कि महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मान्य जाति, घुमंतू जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग (जाति प्रमाण पत्र जारी करने का विनियमन और उसका सत्यापन) अधिनियम, 2000 और उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों, 2012 के अनुसार, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक प्रवेश के साथ-साथ सरकारी सेवाओं आदि के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। हालाँकि, चूँकि कुछ उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि उनके शैक्षणिक प्रवेश में कोई बाधा न आए।

यह रियायत अनुसूचित जातियों, विमुक्त जातियों, घुमंतू जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों पर लागू होगी। उक्त शैक्षणिक संस्थानों (इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित) में प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों को जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवेदन की तिथि से दो माह की अवधि दी जा रही है। सरकारी निर्णय में उल्लेख किया गया है कि संबंधित अभ्यर्थी को आवेदन की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक द्वारा जगजीवन राम अस्पताल में अत्याधुनिक सीटी और एमआरआई स्कैन केंद्र का उद्घाटन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

रेलवे बोर्ड के रेलवे स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. जगदीश चंद्र ने 04 सितंबर, 2025 को पश्चिम रेलवे के जगजीवन राम अस्पताल , मुंबई का दौरा किया। इस अवसर पर डॉ. जगदीश चंद्र ने अस्पताल परिसर में अत्याधुनिक सीटी और एमआरआई स्कैन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता, पश्चिम रेलवे की प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉ. कोंडा अनुराधा, चिकित्सा निदेशक/जेआरएच डॉ. ममता शर्मा सहित पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ चिकित्सक, अधिकारी और यूनियन प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे, अस्पताल स्थित नया सीटी एवं एमआरआई केंद्र उन्नत चिकित्सा इमेजिंग सुविधाओं से सुसज्जित है, जो रोगियों की सुविधा और नैदानिक दक्षता के लिए डिज़ाइन की गई हैं। उन्नत 3ऊ एमआरआई मशीन तेज़ स्कैन समय के साथ बेहतर सटीकता प्रदान करती है, जबकि 128-स्लाइस सीटी स्कैनर कम विकिरण जोखिम के साथ उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें प्रदान करता है, जिससे

रोगी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यह सुविधा एस्काग संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के साथ एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (स्थापना, संचालन, रखरखाव और सेवाएँ प्रदान करना) के तहत स्थापित की गई है। उद्घाटन के बाद डॉ. जगदीश चंद्रा ने कर्मचारियों से बातचीत की, सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना के तहत निर्मित सुविधाओं की समीक्षा की और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने परियोजना के समय पर पूरा होने पर संतोष व्यक्त किया और रेलवे लाभार्थियों के लाभ के लिए उन्नत नैदानिक तकनीक लाने के लिए पूरी टीम को बधाई दी।

रेल मंत्रालय के अधीन पश्चिम रेलवे का एक क्षेत्रीय अस्पताल, जगजीवन राम अस्पताल , 361 बिस्तरों की क्षमता वाला एक प्रमुख तृतीयक स्तर का रेफरल अस्पताल है। यह बुनियादी विशेषज्ञताओं और सुपर-स्पेशलिटी विषयों में व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है, जिसमें गास्ट्रोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, संयुक्त प्रतिस्थापन सर्जरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, यूरोलॉजी, रीनल ट्रांसप्लांटेशन, ऑन्कोसर्जरी, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन और बहुत कुछ शामिल है।

नवनिर्मित सीटी एवं एमआरआई केंद्र, सटीक निदान इमेजिंग प्रदान करने, विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय स्थितियों में उपचार योजना बनाने और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुशल पेशेवरों और आधुनिक तकनीक के साथ, यह सुविधा रोगी देखभाल को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ करेगी और हजारों रेलवे कर्मचारियों, उनके परिवारों, साथ ही आसपास के क्षेत्रों के रोगियों को लाभान्वित करेगी।

चित्रनगरी में 'फिल्म अध्ययन मंडल' पहल लागू की जाएगी- मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार

मुंबई। गुणवत्तापूर्ण फिल्में देखने वाले दर्शक तैयार करने और सिनेमा प्रेमियों को प्रसिद्ध पुरानी फिल्मों का आनंद लेने में सक्षम बनाने के लिए, सांस्कृतिक कार्य मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने घोषणा की है कि आने वाले दिनों में दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी के माध्यम से 'फिल्म अध्ययन मंडल' नामक एक अनूठी पहल लागू की जाएगी। उन्होंने यह घोषणा उस समय की जब दादासाहेब फाल्के गणेशोत्सव के अवसर पर चित्रनगरी में राजा के दर्शन करने आए थे। चित्रनगरी में गणेशोत्सव का यह 32वाँ वर्ष है।

मंत्री एडवोकेट शेलार ने कहा कि सांस्कृतिक कार्य विभाग और महाराष्ट्र फिल्म, रंगमंच एवं सांस्कृतिक विकास निगम फिल्म निर्माताओं के उत्थान के लिए निरंतर विभिन्न योजनाओं, पहलों और अभियानों को क्रियान्वित कर रहे हैं। इस पहल से न केवल गुणवत्तापूर्ण फिल्में देखने वाले दर्शक तैयार होंगे, बल्कि इस पहल के माध्यम से सिनेमा प्रेमियों को बड़े पर्दे पर पुरानी, ??गुणवत्तापूर्ण मराठी फिल्में देखने का अवसर भी मिलेगा।

निगम के सहयोग से सह्याद्री वाहिनी पर गुणवत्तापूर्ण मराठी फ़िल्में प्रसारित करने की पहल भी शुरू की जाएगी। मंत्री एडवोकेट शेलार ने आशा व्यक्त की कि इस पहल से मराठी सिनेमा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर निगम की प्रबंध निदेशक स्वाति म्हसे पाटिल, संयुक्त प्रबंध निदेशक प्रशांत सजनीकर, सुप्रसिद्ध निर्देशक-निर्माता सुभाष घई, अभिनेता मिलिंद दस्ताना और अभिनेत्री रूपाली गांगुली उपस्थित थे।

मध्य रेलवे के महाप्रबंधक धरमवीर मीणा द्वारा भुसावल मंडल में अत्याधुनिक यूनिफाइड कवच कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ

भुसावल। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री धरमवीर मीणा ने आज भुसावल मंडल में अत्याधुनिक यूनिफाइड कवच कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया।

यह आधुनिक केंद्र भुसावल मंडल के 134 स्थानों पर स्थापित कवच प्रणाली की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु एक केंद्रीय हब के रूप में कार्य करेगा। उन्नत तकनीकों और विशेष नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम से सुसज्जित यह केंद्र वास्तविक समय में पर्यवेक्षण, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा रेल संचालन में सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा।

इस केंद्र की एक विशेषता फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट सुविधा है, जिसके माध्यम से कवच प्रणाली की लॉजिक का इन-हाउस परीक्षण, सत्यापन एवं प्रमाणीकरण किया जा सकेगा। इससे कवच प्रणाली के अधिक विश्वसनीय, सटीक और तीव्र कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। इस सेंटर के उद्घाटन के साथ ही मध्य रेलवे ने अत्याधुनिक सुरक्षा समाधानों को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य समयपालन में सुधार, जोखिमों को कम करना और यात्रियों की यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाना है।

दुषखेड़ा स्टेशन पर कवच प्रणाली का निरीक्षण

इसी अवसर पर श्री धरमवीर मीणा, महाप्रबंधक, मध्य रेलवे ने दुषखेड़ा स्टेशन का दौरा कर कवच प्रणाली की स्थापना का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने रिले रूम एवं स्टेशन मास्टर पैनल पर स्थापित कवच उपकरणों का अवलोकन किया तथा कवच टॉवर और फील्ड इंस्टॉलेशन की जांच की। महाप्रबंधक ने तकनीकी टीमों को कवच उपकरणों के रख-रखाव, विश्वसनीयता एवं मजबूती पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि सुरक्षा प्रणाली का सुचारु संचालन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कार्य, समय पर कमीशनिंग तथा यात्रियों की सुरक्षा हेतु इस प्रणाली के अधिकतम लाभ उठाने पर बल दिया।

यह निरीक्षण मध्य रेलवे की परिचालन सुरक्षा को बढ़ाने, समयपालन में सुधार लाने एवं यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भुसावल मंडल रेल अस्पताल में मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर का उद्घाटन

महाप्रबंधक, मध्य रेलवे द्वारा भुसावल मंडल रेल अस्पताल में नव-निर्मित मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर का भी शुभारंभ किया गया। इस सुविधा से रेलकर्मियों एवं उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक विस्तार एवं गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। अस्पताल प्रबंधन एवं तकनीकी दल के उत्कृष्ट कार्य हेतु महाप्रबंधक ने सराहना व्यक्त की।

इस अवसर पर एम.एस. उप्पल, प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर, श्री एस.एस. गुप्ता, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, श्री पुनीत अग्रवाल, मंडल रेल प्रबंधक भुसावल सहित मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

2022 के हिट-एंड-रन मामले को लेकर अदालत सख्त, ढुलमुल जांच के लिए मुंबई पुलिस को लगाई फटकार

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीन साल पहले हुए हिट-एंड-रन मामले की जांच में ढुलमुल रवैया अपनाने पर मुंबई पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि पुलिस जांच अपेक्षित मानकों पर खरी नहीं उतरी और केवल अदालत के दखल के बाद ही मामले में कुछ तेजी आई।

न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम की खंडपीठ ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि जांच अधिकारी का रवैया 'चौंकाने वाला और निंदनीय' है, इसलिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अदालत ने मामले की सुनवाई में तेजी लाने और एक साल के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया।

पुलिस पर जांच में गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप

यह आदेश 20 वर्षीय पीड़ित की मां की याचिका पर दिया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने जांच में कोई गंभीरता नहीं दिखाई और न ही अब तक ट्रक और उसके चालक का पता लगाया गया। याचिका के मुताबिक, अगस्त 2022 में मलाड इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीड़ित के स्कूटर को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

पीड़ित की मां की याचिका पर नए सिरे से शुरू हुई जांच

अक्तूबर 2023 में, पुलिस ने स्थानीय अदालत में 'ए' समरी रिपोर्ट (आरोपी की पहचान न हो पाने की स्थिति) दायर की। लेकिन पीड़ित की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को फिर से खोला और नए सिरे से जांच शुरू की। पिछले महीने, हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया गया है।

मामले में पुलिस की लापरवाही बेहद गंभीर

अदालत ने अपने तीन सितंबर के आदेश में कहा, '17 अगस्त 2022 को एक युवक की जान चली गई, लेकिन आरोपी का पता लगाने और आरोपपत्र दाखिल करने में पुलिस को तीन साल लग गए। पुलिस की यह लापरवाही बेहद गंभीर है।' अदालत ने कहा कि यह समझ से परे है कि पिछले तीन वर्षों में पुलिस ने ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए, जो हाल ही में उठाए गए। साफ है कि अदालत की चेतावनी के बाद ही जांच में तेजी आई।

जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करें पुलिस महानिदेशक

हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी के रवैये को निंदनीय बताते हुए पुलिस महानिदेशक को उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही निचली अदालत को एक साल के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश भी दिया गया।

अजित पवार ने बोला हमला

'विपक्ष ने फायदा उठाने की कोशिश की, मुद्दा सुलझने पर साध ली चुप्पी'

पुणे। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने हाल ही में हुए मराठा आरक्षण आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने मामला सुलझा दिया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उपमुख्यमंत्री पवार पुणे में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। दरअसल, मनोज जरांगे ने 29 अगस्त को मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने जरांगे की अधिकांश मांगों को मान लिया, जिसके बाद उन्होंने मंगलवार को भूख हड़ताल वापस ले ली। सरकार ने मराठा समुदाय के सदस्यों को उनकी कुनबी विरासत के

ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा करते हुए एक आदेश भी जारी किया।

लोगों के लिए काम करने का हमारा निरंतर प्रयास

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि लोगों ने हमें भारी बहुमत देकर सत्ता में बिठाया है। इसलिए हमारा निरंतर प्रयास है कि हम उन्हें सभी लाभ प्रदान करके उनके लिए काम करें। पवार ने कहा कि कभी-कभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन हम हमेशा उन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करते हैं। उपमुख्यमंत्री पवार ने मराठा आरक्षण आंदोलन का हवाला देकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा सरकार पर निशाना साधने का मौका तलाशता रहता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने पिछले तीन-चार दिनों में मुंबई में जो कुछ हुआ, उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की और प्रेस में जाकर अपने विचार व्यक्त किए।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख पवार ने कहा कि चूंकि राज्य सरकार ने आंदोलन पर प्रभावी प्रतिक्रिया दी, इसलिए विपक्ष चुप हो गया। उन्होंने कहा, 'कुछ लोग अभी भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।'

उपमुख्यमंत्री पवार ने राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, 'नगरीय निकाय चुनाव नजदीक हैं, इसलिए जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव भी होने की संभावना है। हमारे अनुमान के अनुसार, इनमें से कुछ स्थानीय निकाय चुनाव जनवरी में हो सकते हैं। यह केवल एक अनुमान है, क्योंकि चुनावों की घोषणा करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है।'

सम्पादकीय

तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर से हिमालय पर बढ़ रही हैं झीलें, क्या हम तबाही के करीब पहुंच रहे हैं?

हिमनदों का तेजी से पिघलना जलवायु परिवर्तन और इसके परिणामस्वरूप आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का संकेत है। इससे विनाशकारी बाढ़, जल संकट, समुद्र के स्तर में वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन जैसे संकट की स्थिति और गंभीर हो सकती है। यह भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। हिमनदों के पिघलने से पहाड़ों पर नई झीलें बन रही हैं और पहले से बनीं झीलों का दायरा भी बढ़ रहा है, जो कभी भी आसपास के इलाकों में भयंकर तबाही मचा सकती हैं। केंद्रीय जल आयोग की हालिया रपट में कहा गया है कि भारत के हिमालयी क्षेत्र में 432 हिमनद झीलों का आकार चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। इस वर्ष जून के दौरान इन झीलों के जल क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। सवाल यह है कि ये झीलें बढ़ते पानी का दबाव आखिर कब तक झेल पाएंगी? ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में जल का यह अथाह भंडार बड़ी आपदाओं का कारण बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि इन हिमनद झीलों का गहन अध्ययन किया जाए और इनकी नियमित रूप से निगरानी की जाए।

केंद्रीय जल आयोग की रपट के मुताबिक, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं और वहां बनी झीलों का आकार लगातार बढ़ रहा है। भारत में हिमनद झीलों का कुल क्षेत्रफल वर्ष 2011 में 1, 917 हेक्टेयर था, जो वर्ष 2025 में बढ़ कर 2, 508 हेक्टेयर हो गया। यानी इन झीलों के क्षेत्रफल में 30.83 फीसद की वृद्धि हुई है, जो आसपास की आबादी के लिए कभी भी प्रलयकारी साबित हो सकती है।

अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक 197 विस्तारित हिमनद झीलें हैं। इसके बाद लद्दाख में 120, जम्मू-कश्मीर में 57, सिक्किम में 47, हिमाचल प्रदेश में छह और उत्तराखंड में पांच हिमनद झीलों का क्षेत्रफल बढ़ा है। देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान और दून विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में भी पाया गया है कि उत्तराखंड में हिमनदों के पिघलने से बन रही झीलों में मिट्टी, मलबा और पत्थर भी जमा हो रहे हैं। प्रदेश में पिछले दस वर्षों में हिमनद झीलों की संख्या 19.2 फीसद तक बढ़ी है। इससे साफ है कि खतरा लगातार बढ़ रहा है।

वैज्ञानिक अध्ययनों से यह बात साफ हो चुकी है कि बढ़ता वैश्विक ताप और जलवायु परिवर्तन हिमनदों के पिघलने का मुख्य कारण है। इसका नतीजा न केवल विनाशकारी बाढ़ के रूप में देखने को मिल सकता है, बल्कि गंभीर जलसंकट जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाकर और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर सतत विकास के माडल पर ध्यान केंद्रित किया जाए। सरकार, समाज, विज्ञान और जनमानस को मिल कर इस चुनौती से निपटने के उपायों पर काम करना होगा।

जिन पर्वतीय इलाकों में हिमनद झीलों का विस्तार हो रहा है, वहां निचले इलाकों में रह रहे समुदायों के लिए वास्तविक समय पर आधारित निगरानी प्रणाली और उपग्रह-आधारित सतर्कता एवं पूर्व-चेतावनी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही पहाड़ों पर ऐसी गतिविधियों को भी सीमित करने की अत्यंत जरूरत है, जिनसे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जो भविष्य में किसी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है।

जब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है तब नौकरियों के अवसर कम क्यों हो रहे हैं?

देश के आर्थिक विकास का पैमाना कुछ इस तरह होना चाहिए, जिसमें सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक समानता, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, गरीबी और भुखमरी में गिरावट, सामाजिक असमानताओं में कमी, रोजगार की उपलब्धता और प्रति व्यक्ति खुशहाली हो। एक समृद्ध लोकतंत्र में आर्थिक प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जहां व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि हो और समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास संभव हो। विकास का माडल ऐसा हो, जिसमें रोजगार के अवसर, गरीबों का उत्थान और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित हो सके तथा महंगाई की दर कम रहे। भारत की आर्थिक विकास दर लगातार बढ़ रही है। आने वाले तीन वर्षों में देश के पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बन जाने की उम्मीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा।

एशियाई विकास बैंक के मुताबिक, भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष में 6.5 फीसद और 2026 में 6.7 फीसद की दर से बढ़ने की संभावना है। ऐसे में तेजी से आगे बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। भारतीय व्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक असमानता, घटते संसाधन और बढ़ती जनसंख्या है। एक तरफ कहा जा रहा है कि देश का आर्थिक विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है, दूसरी ओर बढ़ती बेरोजगारी दर चिंता का विषय बनी हुई है।

इस वक्त बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है, जो देश के संपूर्ण विकास में अवरोधक है। उसी अर्थव्यवस्था को संतुलित माना जाता है, जिसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हों। संगठित एवं असंगठित

क्षेत्रों में रोजगार के अवसर घट रहे हैं। जुलाई 2015 से जून 2016 और अक्तूबर, 2022 से सितंबर, 2023 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के 18 लाख असंगठित उद्यम बंद हो गए हैं। इस कारण करीब 54 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल कार्यबल तथा जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहां युवाओं की आबादी अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा है। हाल में जारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रपट के मुताबिक, देश में पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.6 फीसद, जबकि महिलाओं में 5.8 फीसद है। देश में 15-29 आयु वर्ग के युवाओं में इस वर्ष अप्रैल में बेरोजगारी 13.8 फीसद से बढ़कर मई में 15 फीसद हो गई। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अप्रैल में 17.2 फीसद से बढ़कर मई में 17.9 फीसद हो गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अप्रैल के 12.3 फीसद की तुलना में मई में 13.7 फीसद थी।

मगर हमारे यहां जनसंख्या और श्रमबल क्षमता अधिक होने के बावजूद आर्थिक असमानता भी अन्य देशों की तुलना में अधिक है। देश में बढ़ती बेरोजगारी के साथ ही आर्थिक असमानता विकास की राह बड़ी बाधक है। आक्सफैम-2024 की एक रपट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके मुताबिक, पिछले कई वर्षों से भारत समेत विश्व में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। यह आर्थिक तंत्र के लिए बहुत निराशाजनक और चिंताजनक बात है। आर्थिक असमानता के मामले में भारत के संदर्भ में कोई विशेष सुधार नहीं दिखाई देता है।

आंकड़ों के मुताबिक, भारत की कुल संपत्ति का चालीस फीसद हिस्सा देश के एक फीसद अमीर लोगों के पास है। वर्तमान में भारत के इक्कीस सबसे अमीर अरबपतियों के पास देश के सत्तर करोड़ लोगों से ज्यादा संपत्ति है। आधी आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का केवल तीन फीसद है। यहां अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में वर्ष 2020 में 102 अरबपति थे, 2022 में 166 और 2023 में यह आंकड़ा 200 के करीब पहुंच गया है। इस तरह की आर्थिक असमानता से गरीबी, बेरोजगारी एवं भुखमरी बढ़ती है और देश का सर्वांगीण विकास रुक जाता है।

अगर भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों पर गौर करें तो इसे दूर करने संबंधी प्रयास निराशाजनक नजर आते हैं। बेरोजगारी दर में उतार-चढ़ाव से देश के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इंडिया स्किल्स रपट-2025 के अनुसार, भारत में स्नातकों के बीच रोजगार योग्यता बढ़ कर 54.81 फीसद हो गई है। वहीं, 'नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क' की रपट से पता चलता है कि भारत में हर वर्ष पचास लाख युवा उच्च शिक्षा की ओर रुख करते हैं, जिनकी उम्र करीब उन्नीस-बीस वर्ष होती है। ये युवा अपनी स्नातक की पढ़ाई लगभग 24 वर्ष की उम्र तक पूरी कर लेते हैं। जबकि भारत में पच्चीस वर्ष से कम उम्र के युवाओं में स्नातक स्तर पर बयालीस फीसद बेरोजगार हैं।

परास्नातक की पढ़ाई करने के बाद या जिनकी उम्र पच्चीस से उनतीस वर्ष के बीच है, उनमें बेरोजगारी 22.8 फीसद है। इसी तरह तीस से पैंतीस वर्ष उम्र के पढ़े-लिखे युवाओं में बेरोजगारी 9.8 फीसद है। इससे ऊपर की उम्र के शिक्षित लोगों में बेरोजगारी दर लगभग पांच फीसद है। देश में पिछले दस वर्षों में बेरोजगारी दर में लगातार वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2014 में यह 5.44 फीसद और 2020 में आठ फीसद थी। वर्ष 2023 के अक्तूबर में बेरोजगारी दर 10.1 फीसद पर पहुंच गई थी।

भारत में श्रमबल की भागीदारी लगभग 46 फीसद है। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर नजर डालें तो इसके कई कारण स्पष्ट नजर आते हैं। इनमें जनसंख्या वृद्धि प्रमुख कारण है। कोविड महामारी से उत्पन्न आर्थिक दिक्कतें, व्यावसायिक कौशल की कमी, खराब शैक्षिक उपलब्धियां, कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता, विनिर्माण क्षेत्र में कम निवेश और अपर्याप्त ढांचागत विकास माध्यमिक क्षेत्र में नौकरी के अवसरों को सीमित करता है। भारत में आर्थिक विकास दर बढ़ी, उद्योगों से लाभ हुआ, संवेदी सूचकांक में उछाल भी आया, पर रोजगार के अवसरों में अपेक्षाजनक बदलाव नहीं हुआ।

सरकारी मुहिम 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत विदेशी कंपनियां भारत में अपने उत्पाद बेचने के उद्देश्य से यहां उद्योग लगा रही हैं, पर ये युवाओं को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने में सफल साबित नहीं हो पा रही हैं। भारत में रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम दर्जे के उद्योग सृजित करते हैं।

एक अनुमान के मुताबिक, देश में लघु एवं मध्यम उद्योग कुल चालीस फीसद रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इन क्षेत्रों को भी सरकारी नीतियों से अपेक्षाजनक प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। भारत में सबसे ज्यादा साठ फीसद श्रमशक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में है। वर्तमान समय में देश में रोजगार की दर चालीस फीसद है। यानी यहां पर सौ लोगों में से सिर्फ चालीस लोगों के लिए काम उपलब्ध है, बाकी साठ लोगों के पास कोई काम नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि जब देश में आर्थिक विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो रोजगार के स्रोत क्यों घट रहे हैं। देश में रोजगार की उपलब्धता कम होने से प्रतिभा संपन्न युवाओं का अन्य देशों में पलायन होने लगता है, जो देश के लिए कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में जरूरी है कि एक स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर रोजगार सृजन, आर्थिक समानता लाने और प्रतिभा संपन्न युवाओं की श्रमशक्ति का सदुपयोग करने की दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जाएं।

नये युग में जापान-भारत मैत्री, भारत बनेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब

अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में ठहराव आने और टैरिफ विवाद के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से दोनों देशों के मध्य जहां मैत्री प्रगाढ़ हो रही है वहीं नए अवसरों का युग भी प्रारंभ हो रहा है। जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गायत्री मंत्र तथा संस्कृत के श्लोकों के साथ अत्यंत भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान की धरती पर पैर रखने से पहले जापान ने अमेरिका के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता स्थगित करके वार्ताकारों के दल की वाशिंगटन यात्रा टाल दी। यह एक अत्यंत साहसिक और कड़ा संदेश है कि अब विश्व के देश अमेरिका के आगे नतमस्तक होने वाले नहीं हैं। ज्ञातव्य है कि अमेरिका लगातार जापान पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा से पूर्व भी सात बार जापान की यात्रा कर चुके हैं किंतु ताजा यात्रा कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक रही। यात्रा में पहली बार जापान के साथ व्यापक सुरक्षा समझौता हुआ है तथा जापान ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की नीतियों का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ शिखर वार्ता की। इस वार्ता का उद्देश्य भारत और जापान के बीच व्यापार, निवेश और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों सहित समग्र द्विपक्षीय संबधों को और विस्तारित करना था। दोनो देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के कारोबारी समूहों को भारत में निवेश का आमंत्रण दिया। उन्होंने जापान में बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि जापान तकनीक का पावर हाउस है और भारत प्रतिभा की महाशक्ति। दोनों देश मिलकर इस सदी की प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं विशेष रूप से एआई, सेमी कंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी व अंतरिक्ष, मेट्रो नेटवर्क, विनिर्माण तथा स्टार्टअप के क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि जापान हमेशा से भारत की विकास यात्रा में एक प्रमुख भागीदार रहा है। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में संभवित सहयोग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा के दौरान 10 साल का आर्थिक रोडमैप तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत जापान भारत में छह लाख करोड़ का निवेश करेगा। इससे पूर्व भारत-जापान शिखर वार्ता के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्र के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं अपितु वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बेहतर विश्व को आकार देने में मजबूत लोकतांत्रिक देश स्वाभविक साझेदार होते हैं। आज हमने अपनी साझेदारी में एक नए और सुनहरे अध्याय की नींव रखी है। हमने अगले दशक के लिए एक रोडमैप बनाया है।

प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे की एक विशेष बात यह भी रही कि भारत -जापान साझेदारी कोजापान में द्विदलीय समर्थन प्राप्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों योशीहिदे सुगा और फूमियो किशिदा से मुलाकात की। उन्होंने वहां के संसद अध्यक्ष व सांसदों के समूह के साथ चर्चा की। एक अनोखी पहल के तहत जापान के 16 राज्यों के गवर्नर ने प्रधानमंत्री से मुलाकात और निवेश आदि पर व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ बुलेट ट्रेन में यात्रा की और भारतीय ड्राइवरों के साथ चर्चा की।अब इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत में भी जल्द ही बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा जिसकी तैयारी चल रही है।

भारत और जापान के बीच रक्षा, मानव संसाधन आदान-प्रदान, डिजिटल नवाचार, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, अंतरिक्ष सहयोग और सांस्कृतिक साझेदारी सहित कुल 21 समझौते हुए हैं जो भारत-जपान मैत्री के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा अधिकांश समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे।

जापान के साथ हुए 21 द्विपक्षीय समझौते ही 21वीं सदी के नए भारत की नई विकासगाथा लिखने वाले हैं। भारत और जापान के मध्य हुई इस अहम साझेदारी का दर्द अमेरिका भूल नहीं पाएगा। उसे भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ने की गलती का निश्चित रूप से पछतावा होगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत -जापान का अगले दशक के लिए संयुक्त दृष्टिकोण का डाक्यूमेंट भी जारी किया है। सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है जिसके अंतर्गत दोनो देश आपसी संसाधनों व तकनीकी क्षमताओं का साझा उपयोग करेंगे। दोनों देशों की सेनाओं के मध्य बेहतर सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। चंद्रयान-5 के लिए भी समझौता हुआ है जिसके अंतर्गत जापान के राकेट से ही अब चंद्रयान-5 लांच होगा। मानव संसाधन के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया है जिसमें दोनों देश पांच वर्षों में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसमें 50 हजार कुशल और अर्ध कुशल पेशेवरों को जापान भेजा जाएगा। यह न सिर्फ व्यापारिक अपितु सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सहयोग को भी बढ़ावा देगा। अब जापान के विश्वविद्यालयों में अधिक से अधिक भारतीय युवा पढ़ाई कर सकेंगे। भारत और जापान के मध्य डिजिटल पार्टनरशिप को बढ़ाने पर भी समझौता हुआ है। मोबिलिटी के क्षेत्र में हाई स्पीड रेल, बंदरगाहों, विमानन और जहाज निर्माण में भी तेजी आएगी।

जापान का नया निवेश न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा अपितु भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा साथ ही भारत के लोगों को बेहतर जीवनशैली के विकल्प भी देगा। भारत-जापान साझेदारी केवल आर्थिक सहयोग नहीं है अपितु यह साझा भविष्य की दिशा में एक मजबूत निवेश है। यह दोनों देशों के लिए समृद्धि और क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना अति महत्वपूर्ण है कि भारत और जापान एक-दूसरे के लिए बने हैं।

नेताओं को सुधारने के लिए बन रहे हैं इंडोनेशिया जैसे हालात

इंडोनेशिया की राजधानी में संसद पहुंचने की कोशिश कर रहे हजारों पत्थरबाज छात्रों पर दंगा पुलिस ने आंसू गैस के कई राउंड दागे। ये छात्र संसद सदस्यों के भव्य भत्तों का विरोध करने के लिए वहां पहुंचे थे। प्रदर्शनकारी हाल की रिपोर्टों से नाराज थे कि प्रतिनिधि सभा के 580 सदस्यों को सितंबर 2024 से प्रति माह 50 मिलियन रुपिया (एसडी 3, 075) का आवास भत्ता मिल रहा है। सांसदों को प्रति महीने दिया जाने वाला भत्ता एक इंडोनेशियाई नागरिक के प्रति महीने आय से 20 गुना ज्यादा है। इंडोनेशिया की संसद के 580 सदस्यों को सितंबर 2024 से 5 करोड़ रुपये (3, 075 डॉलर) आवास भत्ता के तौर पर दिए जा रहे हैं। इंडोनेशिया में भ्रष्टाचार व्याप्त है और कार्यकर्ताओं का कहना है कि 28 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले देश में पुलिस और संसद सदस्यों को व्यापक रूप से भ्रष्ट माना जाता है। नेताओं के रवैये को देखकर लगता है कि भारत में भी देर-सबेर ऐसे हालात बन रहे हैं। मंत्री, सांसद-विधायकों का सही मायने में देश के लोगों की हालत से ज्यादा सरोकार नहीं रह गया है। संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा में चर्चा के लिए 120 घंटे तय थे किन्तु 37 घंटे ही चर्चा हो पाई। हंगामे के कारण कार्रवाई ठप होने से जनता कई सौ करोड़ के धन का नुकसान हुआ। लगातार व्यवधानों के कारण केवल एक तिहाई समय तक ही सक्रिय रूप से चल पाया। इसमें बड़ा हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का रहा। अधिकांश समय हंगामे में बीता, जिससे विधेयक बिना पर्याप्त चर्चा के पारित किए गए। राज्य सभा में 285 सवाल पूछने के बावजूद केवल 14 सवालों का ही जवाब सत्र के दौरान दिया गया। लगातार 20 दिनों तक इंडिया ब्लॉक से जुड़े विपक्षी दलों ने बिहार में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण केमुद्दे पर लोक सभा और राज्य सभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। इसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही काफी बाधित हुई। राज्य सभा के डिप्टी चेयरमैन हरवंश ने मॉनसून सत्र के आखिरी दिन अपने समापन भाषण में कहा कि कुल मिलाकर, सदन केवल 41 घंटे 15 मिनट ही चल पाया। इस सत्र की उत्पादकता निराशाजनक रूप से सिर्फ 38.88 प्रतिशत रही, जो गंभीर आत्मचिंतन का विषय है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुने हुए जनप्रतिनिधी देशहित के लिए कितने गंभीर हैं।

काम नहीं तो वेतन नहीं, संसद में इस मुद्दे पर कोई आवाज नहीं उठाता। किसी भी कारण से संसद का कामकाज हो या नहीं, इससे सांसदों को फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पूरा वेतन-भत्ता मिलता है। काम नहीं करने के आधार पर इसमें कटौती की कोई चर्चा तक नहीं करता। दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश के निर्दलीय सांसद उमेश पटेल अकेले ऐसे सांसद रहे जिन्होंने यह मांग उठाई। उन्होंने कहा था कि अगर सदन नहीं चलता है, तो सांसदों को भत्ता भी नहीं मिलना चाहिए। उनका दावा था कि सांसदों को भत्ता तो मिलता है, लेकिन जनता के काम नहीं हो पाते। उन्होंने आरोप लगाया था कि सत्ता और विपक्ष दोनों की इगो के कारण सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, जबकि विपक्षी दल सरकार को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन में कार्य नहीं होने पर सांसदों का वेतन और अन्य लाभ रोके जाने चाहिए। संसद की कार्रवाई ठप करने के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर आरोपों का ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन जब बात वेतन-भत्ते बढ़ाने की आती है तो सब मिल कर एक हो जाते हैं। इस पर कोई बहस तक नहीं होती। वेतन-भत्तों के एवज में सांसदों की उत्पादकता कितनी रही, इसका विश्लेषण तक नहीं किया जाता। देश जब 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तब उस दौरान मॉनसून सत्र में 79 घंटे भी संसद नहीं चली। देश की संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा में 83 घंटे काम नहीं हुआ। इससे 124 करोड़ 50 लाख रुपए जनता का धन बर्बाद हुआ। राज्यसभा में 73 घंटे ठप रही, इससे 80 करोड़ रुपए व्यर्थ गए। मतलब दोनों सदनों में मिलाकर 204 करोड़ 50 लाख रुपए बर्बाद कर दिए गए। संसद में जहां घंटाभर बैठकर सांसद काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें ही 5-5 साल की जिम्मेदारी देकर जनता भेज देती है। संसद में बैठने वाले 93 प्रतिशत सांसद करोड़पति हैं, जिन्हें अभी एक लाख 24 हजार रुपए हर महीने वेतन मिलता है। संसदीय क्षेत्र भत्ता 84 हजार रुपए होता है। दैनिक भत्ता सांसदों का 2500 रुपए है। वेतन भत्ता जोड़कर हर सांसद को हर महीने दो लाख 54 हजार रुपए जनता के पैसे से दिया जाता है। देशहित के नाम पर हंगामा कर संसद की कार्रवाई ठप करने में सांसद कोई मौका नहीं छोड़ते पर जब बात वेतन-भत्ते बढ़ाने की आती है तो सब एक हो जाते हैं। गत वर्ष संसद सदस्यों के वेतन में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। नया वेतन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी माना गया। इसके साथ ही सांसदों का मासिक वेतन कुछ भत्तों और सुविधाओं के अलावा 1.24 लाख रुपये हो गया है। सरकार का कहना था कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सांसदों के वेतन में वृद्धि की गई। वहीं पूर्व सदस्यों के लिए पांच साल से अधिक की सेवा पर प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की गयी। इसमें कहा गया है कि दैनिक भत्ता 2, 000 रुपये से बढ़ाकर 2, 500 रुपये कर दिया गया है।

पूर्व सांसदों की पेंशन 25, 000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 31, 000 रुपये प्रति माह कर दी गई। पांच साल से अधिक की सेवा पर प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन 2, 000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2, 500 रुपये प्रति माह कर दी गई। 1954 के सांसद वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत उन्हें यह सुविधा दी गई है। हर पांच साल में होता है रिव्यू 2018 के बाद से सांसदों के वेतन और भत्ते की हर पांच साल पर समीक्षा होती है। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है। 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों के लिए कानून में संशोधन किया गया था। सांसदों को विट्ठलभाई पटेल (वीपी) हाउस में हॉस्टल से लेकर मध्य दिल्ली में दो बेडरूम वाले फ्लैट और बंगले तक आवास मिलता है। उन्हें बिजली, पानी, टेलीफोन और इंटरनेट शुल्क के लिए भी राशि दी जाती है। संसद में निरंतर हंगामे के परिणामस्वरूप दोनों सदनों में लंबे समय तक स्थगन होता है जो अंततः सदन में सार्वजनिक नीति के निर्माण को प्रभावित करता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है, जहां नीति पर अपनी राय के साथ हर किसी की अपनी आवाज है, लेकिन ये लंबे समय तक व्यवधान संसद की क्षमता को कम कर रहा है। दिन के अंत में हमें क्या परिणाम मिलता है, और चर्चा से हमें कितना लाभ होता है?

संसद अपने नियम और विनियम बनाती है, विधायी निकायों के प्रभावी कामकाज के लिए उन नियमों और विनियमों का पालन करना सदस्यों पर निर्भर है। ऐसा कब तक होगा? संसद को व्यक्तिगत स्तर और पार्टी स्तर दोनों पर आंतरिक जांच और संतुलन के साथ आना होगा। बार-बार व्यवधान डालने पर आनुपातिक दंड लगाया जा सकता है। एक संसद व्यवधान सूचकांक तैयार किया जा सकता है जिस पर व्यवधानों का स्वतः निलंबन लागू किया जा सकता है। साथ ही संसद के कार्य दिवसों में वृद्धि की जानी चाहिए। लगातार व्यवधान एक नया मानदंड बनता जा रहा है जो पार्टियों के बीच विश्वास की कमी को बढ़ाता है।

पूर्व प्राचार्य डॉ. एस.पी. सिंह बने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद के सदस्य

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज के पूर्व प्राचार्य डॉ. एस.पी. सिंह को उत्तर प्रदेश की अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ की कार्यकारी परिषद का सदस्य नामित किया गया है। यह नियुक्ति विश्वविद्यालय परिषद की 66वीं बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार की गई है। कुलपति प्रो. संजीव मिश्रा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज के प्राचार्य रहते हुए डॉ. सिंह ने शिक्षा, अनुसंधान और रोगी सेवा को नए आयाम दिए। उन्होंने आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित किया, शोध गतिविधियों को मजबूत किया और संस्थान के शैक्षणिक वातावरण को उच्च स्तर तक पहुँचाया।

डॉ. सिंह की नई जिम्मेदारी का स्वागत प्रयागराज और पूरे उत्तर प्रदेश के चिकित्सा जगत ने किया है। सहकर्मियों का मानना है कि उनका अनुभव, दृष्टि और नेतृत्व राज्य की चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा।

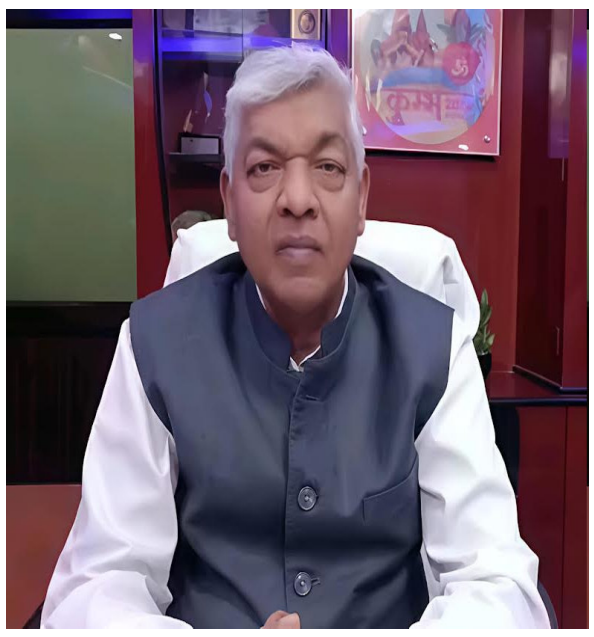

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. वी.के. पांडेय ने कहा, 'यह हमारे संस्थान और पूरे प्रयागराज के लिए गर्व की बात है। डॉ. एस.पी. सिंह हमेशा से उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता और दूरदर्शी सोच के लिए जाने जाते रहे हैं। कार्यकारी परिषद में उनका योगदान निश्चय ही चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के स्तर को और ऊँचाई पर ले जाएगा।'

नियुक्ति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉ. एस.पी. सिंह ने कहा, 'मुझे यह दायित्व मिलना मेरे लिए सम्मान और प्रेरणा दोनों है। मेरा प्रयास रहेगा कि विश्वविद्यालय और प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा को और मजबूत करने के लिए अपने अनुभव का पूरा उपयोग करूँ। प्रयागराज और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमेशा मुझे सहयोग दिया है, यह उपलब्धि उन्हीं के आशीर्वाद और समर्थन का परिणाम है।'

एनटीपीसी स्वर्ण जयंती व शिक्षक दिवस पर मेजा ऊर्जा निगम द्वारा पूर्व सहयोगियों का सम्मान समारोह

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। एनटीपीसी के स्वर्ण जयंती वर्ष एवं शिक्षक दिवस के अवसर पर मेजा ऊर्जा निगम प्रा. लि. (एमयूएनपीएल) द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अशेष कुमार चट्टोपाध्याय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेजा ऊर्जा निगम एवं अपराजिता महिला समाज की अध्यक्षा श्रीमती कृष्णा चट्टोपाध्याय, वरिष्ठ महाप्रबंधकगण, विभागाध्यक्षगण, कर्मचारी एवं उनके परिवारजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशेष कुमार चट्टोपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा कि 'यह समारोह केवल सम्मान का अवसर नहीं, बल्कि कृतज्ञता का प्रतीक है। हमारे पूर्व सहयोगियों की विरासत और सीख ही एमयूएनपीएल एवं एनटीपीसी को भविष्य में और ऊँचाइयों तक ले जाएगी।'

समारोह में एनटीपीसी परिवार के गौरव - पूर्व सहयोगियों एवं उनके परिवारों को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि ये पूर्व सहयोगी ही संगठन के ध्वजवाहक और मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने अपने अनुशासन और समर्पण से एनटीपीसी को भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थापित किया।

कार्यक्रम में एनटीपीसी की 50 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर आधारित लघु फ़िल्म तथा एमयूएनपीएल की प्रगति की कहानी की एक वृत्तचित्र प्रदर्शित की गई। साथ ही वरिष्ठ सदस्यों ने अपने अनुभव व सीख साझा किए, जिन्हें नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बताया गया। समारोह का समापन सभी आमंत्रितों के प्रति आभार ज्ञापन, समूह चित्र और 'जय हिन्द, जय एनटीपीसी, जय एमयूएनपीएल' के उद्घोष के साथ हुआ।

गौरी पुत्र गणेश को लगा मेवा बर्फी का भोग

भक्ति भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ आयोजन

6 सितंबर को निकाली जाएगी भगवान गणेश की विसर्जन शोभा यात्रा

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। नवयुवक संघ गणेश पूजन समिति के तत्वाधान में 15 वां विशाल गणेश महोत्सव के नवें दिवस के अवसर पर शिव पार्क मलाकराज में स्थापित शिव पार्क का राजा गणपति को कार्यक्रम के संयोजक सनी सोनकर ने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्जन आरती करते हुए गौरी पुत्र गणेश को मेवा बर्फी का भोग लगाया।

इस अवसर पर सांसद उज्जवल रमण सिंह ने आरती किया और प्रसाद वितरण किया।

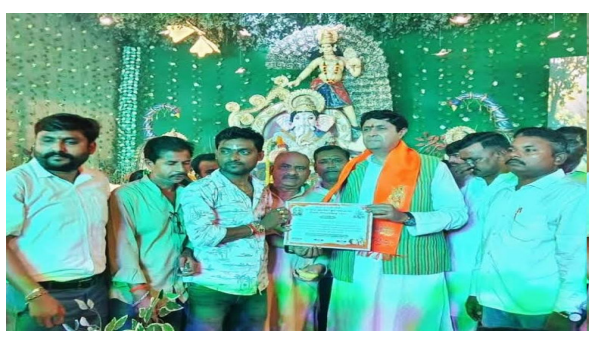

इस अवसर गुरमी म्यूजिकल ग्रुप जागरण पार्टी के गायक कलाकारों के द्वारा भजनों के गीत गाए गए और शानदार झांकी का आयोजन किया गया जो भक्तों को आनंदित किया गया। मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने बताया कि समिति के द्वारा गणेश महोत्सव के 5 सितंबर को सुबह 10 बजे हवन यज्ञ और गुरमी म्यूजिकल ग्रुप भजन मंडली के द्वारा रात्रि 9 :00 बजे के द्वारा भजनों झांकियों की शानदार प्रस्तुति का आयोजन किया जाएगा और लकी ड्रा कूपन का लकी ड्रा खोला जाएगा। इस अवसर पर राजेश केसरवानी, मनोज सिंह, रिंकू जायसवाल, आदि कमेटी के लोग और भक्तगण मौजूद रहे।

पुलिस उपायुक्त गंगानगर व सहायक पुलिस आयुक्त थरवई द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई कर फरियादियों की शिकायतें सुनी गई तथा निस्तारण हेतु सम्बंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

रोटरी क्लब एकेडीमिया द्वारा हर्षोल्लास से मनाया गया शिक्षक दिवस

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। शिक्षक दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब एकेडीमिया ने अपना वार्षिक 'नेशन बिल्डर अवॉर्ड्स' कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न किया। यह आयोजन बेनहर स्कूल के ज़ाहिदा ऑडिटोरियम में हुआ, जहाँ कुल 27 शैक्षणिक संस्थानों के 50 शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में आईईआरटी प्रयागराज की मैनेजमेंट फ़ैकल्टी के डीन प्रोफेसर नजीब अल हसन और क्लब के असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन डॉ. अस्तित्व अग्रवाल उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी ने रोटरी क्लब के सामाजिक कार्यों की सराहना की तथा सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई देते हुए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन रोटेरियन असरा नवाज़ और रोटेरियन अलीना खान ने किया। क्लब के फाउंडर प्रेसिडेंट रोटेरियन तारिक खान और मौजूदा प्रेसिडेंट रोटेरियन डॉ. सैयद नाज़िम, पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन डॉ. अफ़रोज़ जहाँ एवं इमीडियेट पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन आफताब अहमद ने अतिथियों को मोमेंटो भेंट किया। अंत में प्रोजेक्ट डायरेक्टर रोटेरियन शीबा खान ने सभी अतिथियों और शिक्षकों का आभार व्यक्त किया।

सड़क हादसे में घायल बाइक सवार युवक की मौत

प्रयागराज। लेप्रोसी चौराहे के पास रेलवे अंडरपास के नजदीक बुधवार देर रात बाइक सवार युवक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। पुलिस ने घायल को एसआरएन अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाइक सवार किसी वाहन से टकराया या डिवाइडर से, पुलिस इसकी जांच कर रही है। नैनी के तिगनौता, डांडी इलाके में रहने वाला हर्ष भारतीय (22) पुत्र बसंत बुधवार देर रात लगभग 12:30 बजे अपने घर से नए पुल की ओर जा रहा था। जैसे वह लेप्रोसी चौराहे से पहले रेलवे अंडरपास के पास पहुंचा, तभी वह अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। नैनी पुलिस ने घायल को एसआरएन अस्पताल भेजा। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

एनआईआरएफ रैंकिंग में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय को देश में तीसरा स्थान

उच्च रैंकिंग प्राप्त होने पर छात्र मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेंगे-कुलपति

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज को राष्ट्रीय स्तर पर एनआईआरएफ रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। देशभर के मुक्त विश्वविद्यालयों में तीसरी रैंक आने पर कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने हर हर्ष व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी।

कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने बताया कि एन आई आर एफ रैंकिंग मिलने से मुक्त विश्वविद्यालय का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के साथ उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने प्रथम तीन रैंक में अपना स्थान मजबूती से दर्ज कराया है। यह पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनकी प्रेरणा एवं निरंतर मार्गदर्शन से यह सफलता प्राप्त हुई।

प्रोफेसर सत्यकाम ने बताया कि एनआईआरएफ रैंकिंग मुक्त विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और

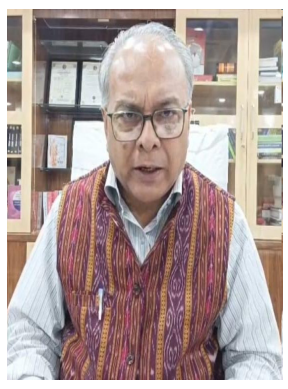

उत्कृष्टता को दर्शाती है, जिससे विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बढ़ती है। उच्च रैंकिंग प्राप्त होने पर अब अधिक से अधिक छात्र मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ आकर्षित होंगे क्योंकि छात्र अक्सर रैंकिंग को अपनी शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं।

प्रोफेसर सत्यकाम ने बताया कि एनआईआरएफ रैंकिंग मिलने पर अब सरकारी निधियन और अन्य वित्त पोषण एजेंसियों से अधिक समर्थन मिल सकेगा। यह रैंकिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने में मदद कर सकेगी जिससे वैश्विक स्तर पर पाठ्यक्रम और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सकेगा। प्रोफेसर सत्यकाम ने बताया कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क एन आई आर एफ शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में कार्य करता है। मुक्त विश्वविद्यालय ने एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए आवेदन किया था। आज शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालय को तीसरी रैंक प्रदान की है। इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों ने कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम के प्रति आभार व्यक्त किया।

भाजपाईयो ने शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर प्रोफेसर डॉ नरेंद्र कुमार सिंह किया गया सम्मान

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर अल्लापुर में विजयंत कोचिंग के उद्घाटन के अवसर पर भव्य रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन

किया गया जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर नरेंद्र कुमार सिंह गौर रहे और उन्होंने विजयतं कोचिंग का उद्घाटन किया। इस अवसर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल भट्ट ने शिक्षक के रूप में पूर्व टैबलेट मंत्री प्रोफेसर डॉ नरेंद्र कुमार सिंह गौर और अन्य शिक्षको को सम्मानित किया। इस अवसर ज्ञानेंद्र गुप्ता, राजेश केसरवानी, सोनी भट्ट, विनीता गुप्ता, मीना राय, हिमांशु तिवारी बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे कार्यक्रम के संयोजक शुभंकर सिंह, रहे।

सांसद फूलपुर/अध्यक्ष, जिला विकास निगरानी समिति (दिशा) की अध्यक्षता वसांसद भदोही की सहअध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। सांसद फूलपुर/अध्यक्ष, जिला विकास निगरानी समिति (दिशा) प्रवीण पटेल की अध्यक्षता व डॉ0 विनोद कुमार बिन्द-सांसद भदोही की सहअध्यक्षता में गुरूवार को सर्किट हाउस के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के द्वाराजनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया एवं विभिन्न कार्यक्रमों योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामीण एवं शहरी आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, यूपीडा, लघु सिंचाई, दुग्ध विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य प्रमुख विषयों परसमिति के द्वारा विस्तार से समीक्षा की गयी एवंसमिति के द्वारा बैठक में कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूर्ण कराये जाने एवं अन्य समस्याओं के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के कार्यों की समीक्षा करते हुएसमिति के द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म की जानकारी ली गयी। उन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म से ही कार्य कराये जाने तथा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि निर्धारित रेशिओ के अनुसार ही पक्के एवं कच्चे कार्य को कराया जाये।सांसद ने मनरेगा के तहत कराये जाने वाले कार्यों मेंजनप्रतिनिधियों का सुझाव लेकर जो काम अत्यंत महत्वपूर्ण व आवश्यक हो, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पहले कराये जाने के लिए कहा है।समिति के द्वारा कहा गया कि मनरेगा के माध्यम से पानी निकासी हेतु नालो एवं सहायक नदियों का जीर्णोद्धार किया जाये, ताकि सिंचाई व पानी की निकासी की समस्या दूर हो।अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि जॉब कार्ड का सत्यापन भी करा लिया जाये, जो लोग कार्य करते है, उन्हीं का भुगतान हो। इसी तरह से ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय का भुगतान भी समय से किया जाये।

समिति ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की समीक्षा में पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के तहत जो भी पात्र लोग है, उनको योजना से अवश्य ही लाभान्वित कराया जाये।समिति के द्वारा यह भी कहा गया कि जिन लोगो की पेंशन बंद की जाये, उनका क्रास सत्यापन अवश्य करा लिया जाये तथा पेंशन बंद होने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये।समिति ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत गांव की सड़के, स्ट्रीट लाइट, विद्युतीकरण सहित अन्य जो भी कार्य शेष है, उन सभी कार्यों को ससमय पूर्ण करा लिया जाये।अध्यक्ष ने कहा कि आगे से जो भी कार्य योजना बनायी जाये, उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सुझाव अवश्य लिया जाये, उस योजना के बारे मेंजनप्रतिनिधियों को जानकारी भी दी जाये।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गतअध्यक्ष ने कहा कि किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच किया जाना सुनिश्चित किया जाये। मिट्टी की जांच कराकर उस मिट्टी के अनुसार किसानों को फसल लगाये जाने के लिए जागरूक करने के लिए कहा है तथा परीक्षण में जो भी कमियां पायी जाये, उनको दूर करने के उपाय भी किए जाये। किसानों को वर्मी कम्पोस्ट, प्राकृतिक खेती एवं फसल चक्र को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जाये। कृषि से सम्बंधित योजनाओं के बारे में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाये, उसके बारे मेंजनप्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए उनको भी कार्यक्रम में शामिल अवश्य किया जाये।अध्यक्ष ने सरकार द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं का लाभ किसानों को दिलाये जाने के लिए कहा है। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरानसमिति ने कहा कि खाद की जो भी समितियां हैं, उनमें समानता से खाद उपलब्ध करायी जाये। किसानों को खाद, बीज सहित अन्य किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाये। इसकी निरंतर निगरानी के करने के निर्देश दिए है। कहा कि ओवर रेटिंग एवं नकली खाद बेचने वालो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये। बैठक में कहा गया कि सभी समितियों को क्रियाशील बनाये रखा जाये।समिति के सदस्यों के द्वारा कहा गया कि आने वाले समय में डीएपी खाद की आवश्यकता होगी।

समिति ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न होने पाये। परंतु कोई भी अपात्र व्यक्ति इसका लाभ भी न लेने पाये। इसका प्राथमिक स्तर पर सत्यापन कराने के लिए कहा है। स्मार्ट सिटी मिशन की समीक्षा के दौरान सिविल लाइंस साई मंदिर के आस-पास एरिया में जो भी कार्य अपूर्ण है, उसको जल्द से जल्द पूरा कराना सुनिश्चित करें।

समिति ने पंचायतीराज योजना में स्वामित्व योजना के तहत घरौंदी वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि घरौंदी का वितरण निष्पक्ष एवं पारदर्शीढंग से किया जाये, इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत न होने पाये। यूपीडा के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान जो सम्पर्क मार्ग भारी वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त हो गये है, उनको शत-प्रतिशत रूप से ठीक करा लिया जाये। बैठक में यह भी कहा गया कि क्षतिग्रस्त होने के उपरांत बनाये गये सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य का सत्यापन भी करा लिया जाये। सत्यापन में यदि कहीं कमी पायी जाये, तो सम्बंधित ठेकेदार के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये।

समिति ने विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि विद्युत विभागसांसद जी से समय लेकर डीसी की बैठक समय-समय पर करायें, ताकि विद्युत विभाग से जुड़ी जो भी समस्यायें है, उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने 10 केवीए के ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराये जाने के लिए कहा। इसके साथ हीसमिति ने विद्युत विभाग, जल निगम एवं पीडब्लूडी को भी आपस में एक समन्वय बैठक कर समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम सचिवालयों में विद्युतीकरण का कार्य अभी तक नहीं हुआ है, जिला पंचायतराज अधिकारी विद्युत विभाग से समन्वय बनाते हुए उन ग्राम सचिवालयों में विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा नेअध्यक्ष सहितसमिति के सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बैठक में जो भी निर्देश दिए गए है, उनका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि योजनाओं के सम्बंध में जब भी कोई कार्ययोजना बनायी जाये, उसमें स्थानीयजनप्रतिनिधियों के सुझावों को भी अवश्य सम्मिलित किया जाये तथा योजनाओं के बारे मेंजनप्रतिनिधियों को समय से जानकारी भी उपलब्ध करायी जाये। इस अवसर परजिला पंचायत अध्यक्ष डॉ0 वी0के0 सिंह, महापौर उमेश चन्द्र गणेश केसरवानी, विधायक फूलपुर दीपक पटेल, विधायक कोरांव डॉ0 राजमणि, विधायक फाफामऊ गुरू प्रसाद मौर्य, विधायक बारा डॉ0 वाचस्पति, विधायक मेजा संदीप सिंह, विधायक हण्डिया हाकिम लाल बिंद, विधान परिषद सदस्य सुरेन्द्र चौधरी एवं डॉ0 के0पी0 श्रीवास्तव, ब्लाक प्रमुखगण सहित अन्यजनप्रतिनिधिगणों के अलावा नगर आयुक्त सांई तेजा, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, परियोजना निदेशक सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

भिवंडी में ओबीसी महासंघ सख्त, सरकार को सौंपा मांग पत्र, आंदोलन की चेतावनी

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी । ओबीसी समाज के अधिकारों और लंबित मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को महासंघ की भिवंडी इकाई ने एक विस्तृत मांग पत्र भिवंडी प्रांत अधिकारी को सौंपते हुए साफ चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं की गईं तो राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा। मांग पत्र में कहा गया है कि मराठा आरक्षण के नाम पर ओबीसी समाज के हिस्से का आरक्षण किसी भी सूरत में कम नहीं किया जाना चाहिए। महासंघ ने तर्क दिया कि ओबीसी समाज पहले ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, ऐसे में उनके आरक्षण अधिकार से किसी प्रकार की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं होगी। महासंघ ने कई अन्य मुद्दों को भी उठाया। इनमें ओबीसी विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना, गरीब परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने, बारिश से हुए कृषि नुकसान की भरपाई, आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण और युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1,000 करोड़ रुपये का विशेष कोष बनाने जैसी मांगें शामिल हैं।

संगठन ने शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का कड़ाई से पालन कराने, ओबीसी छात्राओं को मुफ्त शिक्षा, मेडिकल व इंजीनियरिंग में ओबीसी विद्यार्थियों के लिए अलग सीटें आरक्षित करने पर भी जोर दिया है। इसके अलावा म्हाडा और सिडको की आवासीय योजनाओं में आरक्षण, शहर और तालुका स्तर पर पुस्तकालय निर्माण, डॉ. पंजाबराव देशमुख के नाम पर ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार और एससी-एसटी की तर्ज पर ओबीसी समाज के लिए राज्यस्तरीय योजना शुरू करने की मांग भी की गई है.भिवंडी प्रांत कार्यालय के बाहर हुए एक दिवसीय धरने में महासंघ के नेता भगवान ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। पूर्व विधायक रूपेश दादा म्हात्रे समेत कई प्रमुख चेहरे धरने में मौजूद रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और अंत में हस्ताक्षरित ज्ञापन प्रांत अधिकारी को सौंपा। इस अवसर पर मुख्य रूप से विश्वास थले, डॉ. सोन्या काशीनाथ पाटिल, मनोज गंगे,यशवंत सोरे, रमेश देवेकर, विशू भाऊ म्हात्रे, सुनील बाबू पाटिल, शोभा सुधाकर म्हात्रे, नांदिनी जनार्दन चौधरी, संदिप मनोहर पाटिल, मनोहर तरे आदि बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के पदाधिकारी व स्थानीय लोग ओबीसी समाज के लोग शामिल हुए और अपनी मांगों को? लेकर नारे लगाए। महासंघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों में भिवंडी सहित राज्य के कई हिस्सों में ओबीसी समुदाय की लगातार अनदेखी हुई है। सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित रही, जबकि योजनाओं का वास्तविक लाभ समाज तक नहीं पहुंचा.नेताओं ने साफ कर दिया कि 30 अगस्त 2025 से नागपुर में महासंघ का 'साखली उपोषण' शुरू हो चुका है। यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया, तो राज्यभर में उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा।

फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार से हादसा, एक की मौत, दो गंभीर जखमी

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी शहर के फ्लाईओवर एक बार फिर से मौत का जाल साबित हुए। बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे शांतीनगर पुलिस थाना क्षेत्र स्थित स्व.बालासाहेब ठाकरे फ्लाईओवर पर हुए भीषण सड़क हादसे में 35 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान अंजूर गांव निवासी भावोजी राहुल दादाराम तरे के रूप में हुई है, जो अपनी मोटरसाइकिल से भिवंडी से घर लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक, मिल्लत नगर निवासी अब्दुल्ला इलियास अंसारी अपनी होंडा सिटी कार (एमएच 43 एएफ 1601) तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था। अचानक नियंत्रण खोने पर उसकी कार सामने से आ रही महिंद्रा कार (एमएच 48 बीएच 8198) से जोरदार टकरा गई।टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पीछे से आ रहे भावोजी तरे अपनी बाइक सहित कार से भिड़कर पुल से नीचे जा गिरे। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, कार चालक अब्दुल्ला अंसारी गंभीर रूप से घायल है और महिंद्रा कार चालक महेंद्र आबा पष्टे को भी चोटें आई हैं। दोनों घायलों का इलाज भिवंडी के निजी अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहला हादसा नहीं है। पिछले पांच वर्षों में भिवंडी के विभिन्न फ्लाईओवर से दर्जन भर लोग नीचे गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके, पालिका प्रशासन और यातायात विभाग सुरक्षा उपायों को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। निवासियों का आरोप है कि अन्य शहरों की तरह यहां भी फ्लाईओवर की दीवारों पर सुरक्षा के लिए लोहे की चादर लगाने की मांग सालों से की जा रही है। लेकिन हर बार सिर्फ मरम्मत और डामरीकरण का काम कर खानापूर्ति कर दी जाती है। लगातार ऊँची होती सड़क के मुकाबले अब सुरक्षा दीवार और छोटी दिखाई देने लगी है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। फिलहाल शांतीनगर पुलिस ने होंडा सिटी कार चालक अब्दुल्ला इलियास अंसारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1), 125(अ), 125(ब), 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है,स्थानीय नागरिकों ने हादसे पर गहरा आक्रोश जताते हुए चेतावनी दी है कि अगर समय रहते सुरक्षा दीवारों को मजबूत नहीं किया गया, तो भिवंडी के फ्लाईओवर और भी कई निर्दोषों की जान ले सकते हैं।

' मंत्र भारत' अखबार के खबर का असर

भिवंडी की मुख्य सड़कों से हटाए गए भंगार वाहन

मंत्र भारत

भिवंडी की सड़कों पर खड़े भंगार वाहन, शहर की सुंदरता और स्वच्छता पर लगा दाग

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी (संवाददाता) ।' मंत्र भारत' में प्रकाशित खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला। भिवंडी शहर की मुख्य सड़कों पर खड़े भंगार वाहनों की समस्या को लेकर समाचार प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद पालिका प्रशासन हरकत में आया। आज पालिका प्रशासन ने नारपोली क्षेत्र से सड़कों के किनारे वर्षों से पड़े भंगार वाहनों को जब्त कर भिवंडी मनपा के भंडारगृह में जमा कराया। इन जर्जर और बेकार पड़े वाहनों की वजह से जहां सड़कों की चौड़ाई घट रही थी और ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही थी, वहीं बारिश के दिनों में इनमें जमा पानी मच्छरों का प्रजनन स्थल बन रहा था। नागरिकों की लंबे समय से उठ रही शिकायतों को ' मंत्र भारत' ने प्रमुखता से सामने रखा था।नगरवासियों ने समाचार प्रकाशित होने के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशासन का आभार जताया है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी ऐसे भंगार वाहन सड़कों से हटाए जाएंगे, ताकि शहर की स्वच्छता और सुंदरता बनी रहे।

भिवंडी में भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का भव्य स्वागत

'मोदी और योगी ने उत्तर प्रदेश को बनाया सर्वोत्तम प्रदेश' - विधायक रमेश मिश्रा

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की बदलापुर विधानसभा से भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का भिवंडी आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। खोखा कंपाउंड स्थित कृष्णा कॉम्पलेक्स प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर भारतीय समाज ने उन्हें शाल व पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया। स्वागत की पहल अजय कुमार सीताराम यादव ने की। मंच पर भाजपा नेता विजय किशोर तिवारी, पी.डी.यादव,ओम प्रकाश मौर्या और रऊफ अंसारी सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए विधायक रमेश मिश्रा ने कहा कि वे हर वर्ष गणेश उत्सव के समय मुंबई आते हैं और यहां रह रहे अपने क्षेत्र के लोगों और शुभचिंतकों से भेंट कर उनका हाल-चाल लेते हैं। उन्होंने जौनपुर के पूर्व विधायक लक्ष्मी शंकर को याद करते हुए कहा कि उनके कार्य आज भी गांव-गांव, गली-मोहल्ले में लोगों को प्रेरित करते हैं। मिश्रा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई ऊँचाइयाँ छुई हैं। 'आज यूपी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, सड़क और बिजली हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और महिलाएं व युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं,' उन्होंने कहा। मिश्रा ने श्रीराम मंदिर निर्माण और काशी तीर्थ के विकास को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इन कार्यों पर देश ही नहीं, विदेशों में भी गर्व किया जा रहा है। कार्यक्रम में ब्रिजेश पांडेय, अभिनव शर्मा, मनोज गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता विवेकानंद पांडेय ने किया।

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसलाः

दाभोलकर के बेटे-पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का केस कोल्हापुर ट्रांसफर

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि तर्कवादी नेता नरेंद्र दाभोलकर के बेटे हमीद दाभोलकर और कुछ पत्रकारों को गोवा में मौजूद दक्षिणपंथी संगठन सनातन संस्था से जान का खतरा होने की आशंका 'वाजिब और असली' लगती है। इसी आधार पर कोर्ट ने गोवा के पोंडा कोर्ट में चल रहे मानहानि के मुकदमों को महाराष्ट्र की अदालत में ट्रांसफर कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

सनातन संस्था ने साल 2017 और 2018 में हमीद दाभोलकर और कई पत्रकारों, जिनमें वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले भी शामिल हैं, के खिलाफ मानहानि के मुकदमे दर्ज कराए थे। आरोप था कि उन्होंने संस्था के खिलाफ झूठे और मानहानिकारक बयान दिए और प्रकाशित किए, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। ये सभी मुकदमे गोवा के पोंडा कोर्ट में दर्ज किए गए थे, जहां संस्था का मुख्यालय मौजूद है। हमीद दाभोलकर और पत्रकारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि इन मुकदमों को गोवा से किसी अन्य जगह, खासकर महाराष्ट्र की अदालत में ट्रांसफर किया जाए। उनका कहना था कि गोवा में संस्था का गहरा प्रभाव है और वहां सुनवाई के दौरान उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है।

मुकदमा चलने पर जान का खतरा

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि अगर मुकदमे की सुनवाई गोवा में होती है, तो उनके साथ भी वही हो सकता है जो नरेंद्र दाभोलकर और अन्य विचारकों, गोविंद पानसरे, प्रोफेसर एम. एम. कलबुर्गी और पत्रकार गौरी लंकेश, के साथ हुआ था। इन चारों की अलग-अलग घटनाओं में हत्या कर दी गई थी। सभी लोग अंधविश्वास और

कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाते थे।

बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी

जस्टिस एनजे जमदार ने 3 सितंबर को दिए अपने आदेश (जो 4 सितंबर को सार्वजनिक हुआ) में कहा कि, 'यदि सनातन संस्था और याचिकाकर्ताओं के बीच की दुश्मनी और टकराव को देखा जाए, तो उनकी आशंका वाजिब और वास्तविक लगती है। न्याय की दृष्टि से सही यही होगा कि ये मुकदमे गोवा से महाराष्ट्र की अदालत में ट्रांसफर किए जाएं।' कोर्ट ने इन मामलों को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। हालांकि, संस्था की मांग पर कोर्ट ने 6 हफ्ते के लिए आदेश पर रोक (स्टे) भी दे दी है।

दाभोलकर हत्या केस का जिक्र

कोर्ट ने अपने आदेश में नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड का जिक्र किया। 2024 में पुणे की सेशन कोर्ट ने दो दोषियों को सजा सुनाई थी। उस फैसले में यह भी सामने आया था कि सनातन संस्था और कुछ अन्य दक्षिणपंथी संगठनों ने दाभोलकर की अंधविश्वास विरोधी मुहिम का कड़ा विरोध किया था। गवाहों ने यह साबित किया कि दोषियों का संबंध सनातन संस्था से था। हालांकि, सीबीआई अब तक हत्या के असली मास्टरमाइंड का पता नहीं लगा पाई है। जस्टिस जमदार ने कहा कि सेशन कोर्ट की ये टिप्पणियां इतनी गंभीर हैं कि हमीद दाभोलकर और पत्रकारों के मन में भय होना स्वाभाविक है।

हमीद दाभोलकर और अन्य हत्याओं का संदर्भ

हमीद दाभोलकर इस हत्याकांड में अभियोग पक्ष गवाह रह चुके हैं और आज भी सनातन संस्था की विचारधारा के आलोचक हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसी शख्सियतों की हत्या का सिलसिला इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा देता है।

दिन दहाड़े 9 लाख की चोरी, जूना गौरीपाड़ा सहमा

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। शहर के जूना गौरीपाड़ा इलाके में दिनदहाड़े हुई एक बड़ी चोरी ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। तीन सितंबर को उस्मान रेसिडेंसी की सातवीं मंज़िल पर रहने वाली अफिफा बानो अब्दुल्ला शेख (30) के घर का ताला अज्ञात चोरों ने तोड़ डाला और नकदी व गहनों समेत 9 लाख 5 हजार रुपये पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस के अनुसार वारदात सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच हुई, जब घर पर कोई मौजूद नहीं था। चोरों ने अलमारी को निशाना बनाकर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चुरा ली। घर लौटने पर अफिफा बानो ने टूटा ताला देखा तो उनके होश उड़ गए और तुरंत भोईवाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।भोईवाड़ा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट्स और सुराग जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।इस वारदात ने स्थानीय नागरिकों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की है। फिलहाल मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक शिवाजी पाटिल कर रहे हैं।

हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं अधिकारीः मुख्यमंत्री आदित्यनाथ

लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आए लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश किया कि हर पात्र व्यक्ति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले।

राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में 250 लोगों से मुलाकात की। बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों को इलाज और आवास से संबंधित सरकारी योजनाओं का बड़े पैमाने पर लाभ मिल रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर कोई पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाया है तो उसे भी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।

उन्होंने आश्वासन दिया कि हर समस्या को समयबद्ध, पारदर्शी व संतुष्टिपरक तरीके से हल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गंभीर

बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को भरोसा दिलाया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। बयान के अनुसार सरकार ने पिछले एक वर्ष में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए राहत कोष से 1100 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है।

जरांगे बोले- मराठा आरक्षण के मुद्दे पर धोखा मिला, तो चुनाव में सत्तारूढ़ दलों को चटा देंगे धूल

छत्रपति संभाजीनगर। कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अगर मराठा समुदाय को आरक्षण के मुद्दे पर धोखा मिला, तो वे चुनावों में सत्तारूढ़ दलों को 'धूल चटवा देंगे'। उन्होंने यह भी कहा कि मराठा समाज के सभी लोगों को ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाएगा। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे एक निजी अस्पताल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुंबई में पांच दिन की भूख हड़ताल खत्म करने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह हड़ताल शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर की गई थी।

जरांगे ने मंगलवार को अपनी भूख हड़ताल तब खत्म की, जब महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति गठित करने की घोषणा की, जो मराठा समुदाय के उन लोगों को कुनबी जाति का प्रमाणपत्र देने के लिए काम करेगी, जिनके पास उनके कुनबी वंश की ऐतिहासिक जानकारी या सबूत मौजूद हैं। कुनबी जाति को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में रखा गया है।

'गजट लागू नहीं हुआ तो चुनाव में सत्तारूढ़ दलों को धूल चटाएंगे'

उन्होंने कहा, अगर हैदराबाद और सतारा के राजपत्र (गजट) को एक महीने के भीतर लागू नहीं किया गया,तो

हम सत्तारूढ़ दलों को आने वाले चुनावों में धूल चटा देंगे। मैं धीरे-धीरे यह सुनिश्चित करूंगा कि पूरा मराठा समाज ओबीसी वर्ग में आ जाए। कार्यकर्ता ने कहा कि उनका आरक्षण के लिए संघर्ष पूरे राज्य के मराठाओं के लिए है।

'कोंकण क्षेत्र के मराठाओं को भी लेना चाहिए आरक्षण'

उन्होंने आगे कहा, आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि कोकण क्षेत्र के मराठा अभी भी इस दायरे में नहीं आए हैं। कोकण के लोगों को आरक्षण का लाभ लेना चाहिए, नहीं तो वे 40-50 साल बाद पछताएंगे। उन्हें किसी की बात नहीं सुननी चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को खतरे में नहीं डालना चाहिए। जब पत्रकारों ने उनसे ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी योजनाएं तेजी से लागू करने और आरक्षण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक कैबिनेट उप-समिति बनाए जाने पर प्रतिक्रिया मांगी, तो जरांगे ने कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है।

'हमें कुछ मिलता है, तो मांगें उठाने लगते हैं ओबीसी नेता'

उन्होंने कहा, अगर हमें कुछ मिलता है, तो कुछ ओबीसी नेता मांगें उठाने लगते हैं। वे हमेशा शिकायत करते रहते हैं। लेकिन अगर इससे ओबीसी को फायदा होता है, तो हमें खुशी है। अगर सरकार ओबीसी के लिए ऐसे कदम उठा रही है, तो उन्हें दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों और किसानों के लिए भी ऐसी उप-समितियां बनानी चाहिए।

मंत्री छगन भुजबल ने सरकार के आदेश पर जताई नाराजगी

मराठा आरक्षण का यह भावनात्मक मुद्दा अभी भी सुलझता नजर नहीं आ रहा है। बुधवार को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और प्रमुख ओबीसी नेता छगन भुजबल ने सरकार की ओर से जारी उस आदेश (जीआर) पर खुलकर नाराजगी जताई, जिसके तहत योग्य मराठाओं को कुनबी जाति प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है।

पैट कमिंस चोट के चलते भारत खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, एशेज सीरीज में खेलने की भी उम्मीदें कम

नई दिल्ली (**एजेंसी**)। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस 2025 के सभी सीमित ओवर के क्रिकेट मैचों से बाहर हो गए हैं। कमिंस को कैरैबियाई दौरे के दौरान चोट लगी थी जिसके बाद स्कैन में उनकी लम्बर बोन में खिंचाव का पता चला। कमिंस अब न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ आगामी सीमित ओवर की श्रृंखला से चूक जाएंगे। जिसमें भारत के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाले तीन वनडे मैच भी शामिल हैं।

कमिंस ने चोट के बारे में अपनी भावनाएं सांझा करते हुए कहा, 'अपने करियर के इस पड़ाव पर मुझे लगता है कि मैं 18 या 19 साल की उम्र के मुकाबले अब शायद थोड़ी तेजी से लय पकड़ सकता हूं। उस समय आपको शायद लगता होगा कि आपको कुछ इशेफील्ड शील्ड मैच या वनडे मैच खेलने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मुझे शील्ड मैच खेलने का मौका नहीं भी मिला तो भी मैं लय पकड़ सकता हूं। रिहैब सही से करू तो बड़ी एशेज सीरीज के लिए मैं कुछ जोखिम उठाने और थोड़ा आक्रामक होने के लिए तैयार हूं। इससे बड़ी कोई और सीरीज नहीं।'

कैरेबियाई और ऑस्ट्रेलिया में टी20 और वनडे सहित कई सफेद गेंद के मैचों से चूकने के बावजूद कमिंस रिहैबिलिटेशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उनका लक्ष्य पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज के लिए फिट होना होगा। हालांकि सीरीज से पहले कमिंस को जरूरी आराम की कमी खलेगी और हो सकता है कि वह सीधे अंतरराष्ट्रीय मैदान पर लौटने से पहले केवल एक या दो शेफील्ड शील्ड मैच ही खेल पाएं।

ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने पहले ही कुछ बदलाव कर लिए हैं। ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए आराम दिया है ताकि वह शेफील्ड शील्ड में लंबे स्पैल डाल सकें। इसके अलावा ब्यू वेबस्टर को एक अतिरिक्त सीम गेंदबाजी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है जो तेज गेंदबाजी में योगदान दे सकते हैं। जिससे कमिंस की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी में और गहराई आ सकती है।

धोनी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, टीवी विज्ञापनों के मामले में अमिताभ सहित बड़ी हस्तियों को पछाड़ा

नई दिल्ली (**एजेंसी**)। महेंद्र सिंह धोनी भले ही 5 साल पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हों लेकिन उनका जलवा अभी भी कायम है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2025 में सबसे ज्यादा टीवी विज्ञापन करने वालों में पहला नाम थाला यानि धोनी का है और उन्होंने टीवी विज्ञापनों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए अमिताभ बच्चन, विराट कोहली सहित कई बड़ी हस्तियों को पीछे छोड़ दिया है। टैम एडेक्स की टीवी विज्ञापन रिपोर्ट (जनवरी-जून) के अनुसार धोनी 2025 की पहली छमाही में भारतीय टेलीविजन पर दूसरे सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले सेलिब्रिटी बनकर उभरे हैं। ब्रांड एंडोसमेंट के मामले में धोनी ने केवल 6 महीनों में 43 ब्रांडों के साथ काम कर शीर्ष स्थान हासिल किया, जो पिछले वर्ष के उनके 42 ब्रांडों के आंकड़े को पार कर गया। यह आंकड़ा अमिताभ बच्चन द्वारा 2024 के पूरे वर्ष के लिए किए गए कुल विज्ञापनों से भी ज्यादा है। शाहरुख खान ब्रांड संख्या में धोनी के बाद 35 विज्ञापनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं जबकि दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन 28 विज्ञापनों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। धोनी को प्रतिदिन औसतन 22 घंटे टीवी विज्ञापनों में देखा गया, जो सभी टेलीविजन चैनलों पर कुल विज्ञापनों की संख्या का लगभग 7% था। यह उन्हें भारतीय विज्ञापन जगत के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक बनाता है। सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले टीवी सेलेब्रिटीज़ की सूची में शामिल होने वाले अन्य क्रिकेटरों में विराट कोहली और राहुल द्रविड़ शामिल हैं।

जेपी मॉर्गन भारत में कॉर्पोरेट बैंकिंग को कर रहा मजबूत

इलेक्ट्रिक वाहन और सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित

नई दिल्ली (**एजेंसी**)। जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी भारत में अपनी कॉर्पोरेट बैंकिंग उपस्थिति को मजबूत कर रहा है और इलेक्ट्रिक वाहन, डेटा सेंटर तथा सौर ऊर्जा जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहा है। ये क्षेत्र देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि कंपनियाँ पूंजीगत व्यय बढ़ा रही हैं।

अमेरिकी बैंक के एशिया प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक कॉर्पोरेट बैंकिंग के सह-प्रमुख ओलिवर ब्रिंकमैन ने मुंबई में एक साक्षात्कार के दौरान कहा, 'जैसे-जैसे मांग में स्थिरता आएगी, पूंजीगत निवेश भी शुरू होगा।' उन्होंने बताया कि भारत और जापान बैंक के सबसे तेजी से बढ़ते एशियाई बाजार हैं, जहां कॉर्पोरेट बैंकिंग से होने वाली आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। हालांकि, अमेरिका द्वारा कई भारतीय आयातों पर टैरिफ बढ़ाने से कुछ चिंता बनी हुई है। विश्लेषकों का कहना है कि ये टैरिफ श्रम-प्रधान उद्योगों को प्रभावित कर सकते हैं और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी कर सकते हैं। इसके बावजूद, ब्रिंकमैन ने कहा कि जेपी मॉर्गन भारत में अपने दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण पर कायम है और पिछले दो-तीन वर्षों में बैंक की स्थानीय कॉर्पोरेट बैंकिंग का राजस्व 30% से अधिक बढ़ा है। भारत में जेपी मॉर्गन का कारोबार वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग, भुगतान सेवाएँ और प्रतिभूति सेवाओं तक विस्तृत है। कंपनी के मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में कॉर्पोरेट केंद्र हैं, जो वैश्विक स्तर पर 55,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ तकनीकी और व्यावसायिक समर्थन प्रदान करते हैं। भारत में कॉर्पोरेट बैंकिंग के अवसरों के बावजूद प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। बैंक ऑफ अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि घरेलू मांग और वैश्विक व्यापार की अनिश्चितता के कारण कंपनियाँ बड़े निवेश के फैसले फिलहाल टाल रही हैं।

हॉकी महिला एशिया कप 2025 कार्यक्रम : थाईलैंड के खिलाफ भारत करेगा अपने अभियान की शुरुआत

नई दिल्ली (**एजेंसी**)। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के बाद अब महिला हॉकी टीम एशिया कप 2025 का आयोजन होने जा रहा है। ये टूर्नामेंट 5 से 14 सितंबर तक खेला जाएगा। वहीं भारतीय महिला टीम थाईलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत 5 सितंबर से करेगी। ये टूर्नामेंट चीन के हांग्जो में आयोजित होगा। जो भी टीम इस टूर्नामेंट की विजेता होगी वह 2026 वर्ल्ड कप के लिए सीधे प्रवेश कर लेगी।

वहीं, अनुभवी गोलकीपर सविता और ड्रैग फ्लिकर दीपिका को लगी चोटों से भारतीय टीम कमजोर हुई है। सविता टखने की चोट के कारण बाहर है जो उन्हें अभ्यास सत्र के दौरान लगी थी। दीपिका की जगह साक्षी खेल रही हैं। फॉरवर्ड और ड्रैग फ्लिकर दीपिका ने पिछले कुछ अर्से में शानदार प्रदर्शन किया है। इन दोनों के नहीं खेलने से कप्तान सलीमा टेटे, नवनीत कौर, उदिता, नेहा, शर्मिला देवी और लालरेम्सियामी पर अधिक दारोमदार होगा।

भारतीय टीम : बांसरी सोलंकीऔर बिछू देवी खारीबम (गोलकीपर), मनीषा चौहान, उदिता, ज्योति, सुमन देवी, निक्की प्रधान, इशिका चौधरी, नेहा, वैष्णवी फाल्के, सलीमा टेटे (कप्तान), शर्मिला देवी, लालरेम्सियामी, सुनेलिटा टोप्पो, नवनीत कौर, रूतुजा पिसाल, ब्यूटी डुंगडुंग, मुमताज खान, साक्षी, संगीता कुमारी।

रोहित शर्मा अगले 10 साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलें, सीएसके के खिलाड़ी ने साझा की यादगार स्टोरी

नई दिल्ली (**एजेंसी**)। भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक रोहित शर्मा ने न केवल बल्ले से मैच जिताऊ प्रदर्शन किए हैं बल्कि अपनी कप्तानी से प्रशंसकों और अपने साथियों का दिल भी जीता है। इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए खेलने वाले खलील अहमद चाहते हैं कि रोहित शर्मा को अगले 10 साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलते रहना चाहिए।

खलील ने 2019 में रोहित से जुड़ी एक घटना को याद किया जब वह गेंद के साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट की भलाई के लिए अगले 10 साल तक खेलना चाहिए और यह मेरी निजी राय है। 2019 में, जब हम राजकोट में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेल रहे थे, तो एक बार मेरा दिन अच्छा नहीं रहा और मैं सिर्फ एक विकेट ले पाया, तो वह मेरे पास आए और ड्रेसिंग रूम में मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात की।'

उन्होंने कहा, 'टीम स्टेडियम से निकल रही थी और वह मुझसे बात करने के लिए रुके और मुझे बताया कि मुझे कैसा होना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी क्षमताओं से अनजान हूं।' खलील ने कहा, 'जब हम स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे, तो सभी प्रशंसक रोहित भाई के लिए चिल्ला रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि 'यह सब तुम्हारे लिए भी हो' और मुझे भी यही कामना करनी चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए।'

खलील पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने रोहित शर्मा की विनम्रता को करीब से देखा है। हिटमैन के नेतृत्व में खेलने वाले कई अन्य खिलाड़ियों की तरह, खलील ने भी बताया कि रोहित शर्मा ने उन पर किस तरह का प्रभाव डाला है। खलील ने आगे कहा, 'मैच के बाद उनके जैसे कप्तान का मुझसे इस तरह बात करना मुझे सोचने पर मजबूर कर गया कि वह कितने दयालु इंसान हैं। मैंने उन्हें ऋषभ (पंत) के साथ भी ऐसा ही करते देखा है। मैं कहूंगा, 'क्या आदमी है! क्या कप्तान है!' जब आपका मैच खराब होता है तो लोग आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं, लेकिन एक कप्तान के रूप में वह कुछ और ही हैं।' खलील ने कहा, 'हाल ही में मैं उनसे दलीप ट्रॉफी के दौरान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मिला था और वह बहुत फिट लग रहे थे, इसलिए मैंने उनसे ऐसे ही बने रहने और खेलते रहने के लिए कहा। मैंने अपने जीवन में ऐसा कप्तान और इंसान शायद ही कभी देखा हो। वह एक रत्न हैं और मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान और प्यार है। इस छोटे से इंटरव्यू में सब कुछ बयां करना संभव नहीं है।'

एशिया कप 2025 के लिए यूएई ने किया अपने स्क्वॉड का ऐलान, मुहम्मद वसीम को मिली टीम की कमान

नई दिल्ली (**एजेंसी**)। एशिया कप 2025 के लिए यूएई ने अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। एशिया कप में यूएई की टीम मुहम्मद वसीम की अगुवाई में उतरेगी। एशिया कप 9 से 18 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात के दो शहरों अबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट इस बार टी20 प्रारूप में खेला जाएगा। अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से ये टूर्नामेंट काफी अहम साबित होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में यूएई का पहला सामना भारत से होगा। भारत और यूएई के बीच 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। यूएई 15 सितंबर को अबू धाबी के जायेद क्रिकेट स्टेडियम में ओमान से खेलेगा। उनका आखिरी ग्रुप मैच 17 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के साथ होगा। ग्रुप चरण के बाद टूर्नामेंट सुपर 4 में प्रवेश करेगा, जहां प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें क्वालीफाई करेंगी। सुपर 4 स्टेज 20 से 26 सितंबर तक चलेगा। दुबई में फाइनल खेला जाएगा, जो 28 सितंबर को होना है। मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूज़ा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतिउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह और सगीर खान।

'मौके देकर थक चुकी हूं', शादीशुदा हैं नीलम गिरी, बोलीं- 'मुझे स्वाभिमानी लड़के पसंद हैं', निरहुआ के भाई संग जुड़ चुका नाम

सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी चर्चा में हैं। शो में कंटेस्टेंट्स के बीच तकरार से लेकर प्यार तक सबकुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच हालिया एपिसोड में एंटरटेनमेंट का जोरदार तड़का लगा, जिसमें भोजपुरी क्वीन नीलम गिरी ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से जबरदस्त तड़का लगाया है। इसी एपिसोड में नीलम गिरी और कुनिका सदानंद को अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हुए भी देखा गया। इस दौरान नीलम ने खुलासा किया कि वह शादीशुदा हैं, जो कि लगभग खत्म हो गया है।

'बिग बॉस 19' के हालिया एपिसोड में भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी से कुनिका सदानंद ने पर्सनल लाइफ को लेकर बात की। कुनिका ने उनसे सवाल किया, 'और तुम्हारी क्या कहानी है शादी की?' इस पर भोजपुरी अभिनेत्री हंसने लगती हैं फिर तान्या मित्तल कहती हैं, 'मैंने पूछा था कल तो इसने कहा कि वो जब तैयार होगी तब इसके बारे में बोलेगी।' इस पर कुनिका उनसे फिर सवाल करती हैं, 'अभी है कि नहीं है?'

नीलम गिरी शादी पर बात करने से थोड़ी झिझकती हैं लेकिन, कुनिका के सवाल का जवाब देते हुए कहती हैं, 'लगभग नहीं हैं समझिए। इंसान को मौका देते-देते-देते थेथर (ढीठ) हो गए। लेकिन ये तो भाईछटक्या ही बोलें?' कुनिका कहती हैं, 'कि सुधर जाएगा सुधर जाएगा?' नीलम फिर कहती हैं, 'हां। मुझे स्वाभिमानी लड़के पसंद हैं, जो स्वाभिमानी नहीं हैं वो मेरे बसकी बात नहीं हैं उनके साथ रहना।' इस पर फिर से बॉलीवुड एक्ट्रेस कहती हैं, 'तो उनके पैसे पर जीएंगे।' भोजपुरी एक्ट्रेस कहती हैं, 'वही-वही समझ गए आप। ये सब कहानी है।' इसके बाद कुनिका अपनी 27 साल पुरानी रिलेशनशिप का खुलासा करती हैं और बताती हैं कि कैसे उन्होंने शादीशुदा इंसान को डेट किया और उसके साथ लिव इन में रही लेकिन फिर भी उससे उन्हें धोखा मिला।

गौरतलब है कि नीलम गिरी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी पर पहली बार बात की है। हालांकि, चर्चा जरूर थी कि वो शादीशुदा हैं लेकिन उन्होंने इसके पहले कभी इस पर बात नहीं की थी। नीलम गिरी अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से काफी सुर्खियों में रही हैं। उनके लिंकअप की खबरें काफी रही हैं। भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के भाई प्रवेश लाल यादव के साथ एक्ट्रेस के अफेयर की काफी चर्चा रही है। वर्ल्डवाइड म्यूजिक को छोड़ने के बाद नीलम को प्रवेश का साथ मिला था, जिसके बाद दोनों ने ढेरों म्यूजिक वीडियोज में काम किया, जो हिट रहे। इतना ही नहीं, उनकी जोड़ी कई भोजपुरी फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। इसमें 'इज्जत घर' और 'यूपी 61 गाजीपुर' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रवेश पहले से ही शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं।

'सोलर प्लांट, बड़े गार्डन और लिफ्ट्स', तान्या मित्तल का दावा- जीती हैं ऐश्वर्या राय से भी लग्जरी लाइफ

मुंबई। टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी चर्चा में है। तान्या मित्तल शो में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कंटेस्टेंट बन चुकी हैं। वह अक्सर अपनी लैविश लाइफ के बारे में बात करते हुए नजर आ जाती हैं। उनकी बातें सुनकर ना केवल घरवाले बल्कि दर्शक भी हैरान हो जाते हैं। तान्या के अनुसार, उनके घर में लिफ्ट्स हैं लेकिन, बिल 600 रुपये आता है। इतना ही नहीं, उनके घर में 150 बॉडीगार्ड्स समेत बड़े गार्डन हैं। इसे लेकर उनका दावा है कि इसमें करीब 800 लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ऐश्वर्या राय से भी लग्जरी लाइफ जीने की बात कही, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है।

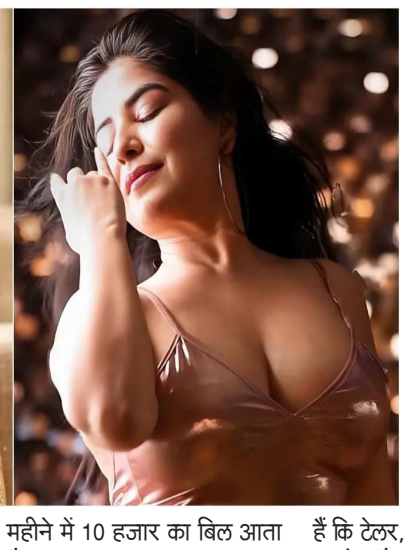

दरअसल, तान्या मित्तल हाल ही के एपिसोड में सिंगर अमाल मलिक से बात करते हुए नजर आईं। उनकी मजेदार बातचीत लोगों ने बड़े ही चाव से सुना। उन्होंने इस दौरान ग्वालियर में अपने परिवार की शानदार लाइफ के बारे में बात की। तान्या ने बड़े ही गर्व के साथ बताया कि उनके घर में कई लिफ्ट्स हैं, जिसके बावजूद भी उनका बिजली का बिल महज 600 रुपये ही आता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे? उन्होंने इसके पीछे के राज के बारे में भी बताया और ऐसा सोलर पैनल की वजह से होता है। तान्या का घर रिन्यूबल एनर्जी से चलता है, जिससे उनके काफी पैसे बचते हैं। तान्या मित्तल इस बातचीत के दौरान खुलासा किया कि उनके घर में सोलर प्लांट से बिजली चलती है। वह बताती हैं कि पूरे साल में उनके घर का बिल 5 हजार भी नहीं आता है। इस पर अमाल मलिक उनसे कहते हैं कि उनके यहां महीने में 10 हजार का बिल आता है।

इतना ही नहीं, तान्या मित्तल दावा करती हैं कि उनके घर में सब्जियां खरीदकर नहीं आती हैं। इसके लिए उनके पास खुद का फार्म हाउस भी है। 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट बताती हैं कि जो सब्जियां उनके खेत में नहीं उगती हैं वो उनके मामा के यहां उगाई जाती हैं। ऐसे में जो भी एक बार सब्जी लेने के लिए खेतों में जाता है तो वह 8 फैमिली को देकर आता है। इसमें मामा-मौसी सबका परिवार शामिल है। सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल ने बताया कि उनके घर पर दूध का भी खर्चा नहीं है। वह बताती हैं कि उनके एक मामा जी हैं, जिनके यहां पर गौशाला है। इसलिए दूध भी उनकी नानी के यहां से आता है। इतना ही नहीं, तान्या बताती हैं कि कपड़े की उनकी खुद की फैक्ट्री है। वह दावा करती हैं कि टेलर, सिलवाना सब कुछ यहां पर होता है। इसलिए ब्रैंड्स खरीदने का खर्च ही नहीं होता है। इसके अलावा तान्या मित्तल ने बताया कि किसी को होटल वगैरह में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है।

उनके कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता है डेवाल्ड ब्रेविस ने महेंद्र सिंह धोनी पर की बात

नई दिल्ली (**एजेंसी**)। दक्षिण अफ्रीका के उभरते हुए बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी की क्रिकेट की महानता के अलावा, पूर्व भारतीय कप्तान की विनम्रता और व्यक्तित्व ने आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनके कार्यकाल के दौरान उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला। आईपीएल 2025 में चोटिल गुरजपनीत सिंह की जगह टीम में शामिल हुए ब्रेविस ने 6 पारियों में 225 रन बनाए जिसमें सीएसके के लिए दो अर्धशतक भी शामिल हैं, जो अंक तालिका में दसवें स्थान पर रही।

ब्रेविस ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के यूट्यूब चैनल पर कहा, 'एमएस (धोनी) के बारे में मैं बस यही कह सकता हूं कि उनकी विनम्रता और एक व्यक्ति के रूप में उनकी शख्सियत मेरे लिए सबसे खास रही। मैदान के बाहर उनका व्यवहार, खिलाड़ियों और लोगों के लिए उनके पास जो समय होता है, वह सब कुछ। उनके कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर वह सो रहे होते हैं, तो सिर्फ उसी समय दरवाज़ा बंद होता है।'

ब्रेविस ने कहा, 'मैंने खुद को कई बार उनके कमरे में पाया, बस वहीं बैठा रहा, चाहे वह कुछ भी कर रहे हों, जैसे उनके शौक के बारे में बात करना, क्रिकेट देखना, और यह देखना वाकई अद्भुत था कि मैदान के बाहर वह क्या करते हैं और जैसे हर कोई जानता है कि वह मैदान पर और प्रशिक्षण में क्या करते हैं और हां, यह बहुत खास है।' सीएसके को आईपीएल में मुश्किल समय का सामना करना पड़ा, लेकिन ब्रेविस ने कहा कि वह इस बात से प्रभावित थे कि कोचिंग स्टाफ उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार करता था। उन्होंने कहा, 'मैंने वहां अपने समय का भरपूर आनंद लिया। फ्लेम (मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग), सभी कोच मैं देखता हूं।'

पश्चिम रेलवे

अधिकारी कक्षों की मरम्मत

मंडल रेल प्रबंधक (पश्चिम रेलवे), पश्चिम रेलवे, छठी मंजिल, इंजीनियरिंग विभाग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400008 ई-निविदा सूचना संख्या: BCT/25-26/208 दिनांक 02/09/2025 आमंत्रित करता है। **कार्य और स्थान:** चर्चगेट - जीएलओ और स्टेशन भवन - अधिकारी कक्षों और विभिन्न अनुभागों की मरम्मत। **कार्य की अनुमानित लागत:** 5,21,62,762.05। **ब्याज राशि:** 4,10,800/-। **जमा करने की तिथि और समय:** 26.09.2025, 15:00 बजे तक। **उद्घाटन की तिथि और समय:** 26.09.2025 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 0554

हमें फॉलो करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

संयुक्त पेंट्री उपकरणों का प्रावधान

उप मुख्य विद्युत अभियंता (पश्चिम), पश्चिम रेलवे कैरिज मरम्मत कारखाना, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013, ई-निविदा सूचना संख्या: EL/WA/PL/2024-25/47R1 दिनांक: 02.09.2025 आमंत्रित करता है। **कार्य का नाम:** कार्य के दायरे और दरों की अनुसूची के अनुसार, पुराने कम्पोजिट पेंट्री उपकरणों को स्ट्रिपिंग सहित कम्पोजिट पेंट्री उपकरणों का प्रावधान और कैरिज रिपेयर वर्कशॉप में एलएचबी राजधानी कोच पर नए कम्पोजिट पेंट्री का डिज़ाइन, आपूर्ति, फिटिंग, परीक्षण और कमीशनिंग। **कार्य की अनुमानित लागत:** 64,22,436.44। **ब्याज राशि:** 1,28,500/-। **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय:** 25.09.2025, 12:00 बजे तक। **निविदा खुलने की तिथि:** 25.09.2025 को 12:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in देखें। 0563

हमें फॉलो करें: facebook.com/WesternRly

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

वृक्ष प्राधिकरण

-सार्वजनिक सूचना-

महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण एवं परिरक्षण अधिनियम, 1975 (जनवरी 2018 तक संशोधित) की धारा 8 (3) (सी) के प्रावधानों के अनुसार, जोन-V के 'एल' वार्ड से 1 प्रस्ताव, 'एम/पश्चिम' वार्ड से 1 प्रस्ताव और जोन-VI के 'टी' वार्ड से 3 प्रस्ताव, अर्थात् कुल 5 वृक्षों को हटाने के प्रस्तावों को नगर आयुक्त, अध्यक्ष, वृक्ष प्राधिकरण, बीएमसी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा (8) की उपधारा (6) के अंतर्गत अनुमोदित किया जाता है।

उपर्युक्त प्रस्तावों में काटे जाने/रोपण हेतु वृक्षों की जानकारी बीएमसी वेबसाइट https://portal.mcgm.gov.in/About us Ward/Department Manuals/Gardens & Tree Authority पर उपलब्ध है। 54 (एल), 55 (एम/डब्ल्यू), 56 (टी), 57 (टी), 58 (टी)

उद्यान अधीक्षक एवं वृक्ष अधिकारी
अधीक्षक कार्यालय, उद्यान और वृक्ष अधिकारी,
दूसरी मंजिल, हम्बोल्ट पेंगुइन बिल्डिंग,
वी.जे.बी. बॉटनिकल उद्यान और चिड़ियाघर, सेंट.सावता माली मार्ग,
बायकुला (पूर्व), मुंबई-400 027
दूरभाष. क्रमांक 23742162
ईमेल-sg.gardens@mcgm.gov.in

-एसडी-

पीआरओ/1478/विज्ञा./2025-26 — उद्यान अधीक्षक एवं वृक्ष अधिकारी

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ धोएं।

सही भोजन बेहतर जीवन की आधारशिला - डॉ जी एस तोमर

कानपुरः आरोग्य भारती कानपुर प्रांत द्वारा रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट इन्दिरा नगर, कल्याणपुर, कानपुर में ' वर्तमान स्वास्थ्य चुनौतियाँ एवं स्वस्थ जीवनशैली' विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विश्व आयुर्वेद मिशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रो.(डॉ.) जी एस तोमर उपस्थित रहे । कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ एस बी मिश्रा ने की । आरोग्य भारती कानपुर प्रांत के अध्यक्ष डॉ बी एन आचार्य ने अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया । अपने उद्बोधन में डॉ तोमर ने आयुर्वेदीय जीवनशैली को स्वस्थ भारत की आधारशिला बताया । उन्होंने कहा हज़ारों वर्ष पूर्व महर्षियों ने अपनी तपो साधना से जिस जीवनशैली का वर्णन किया है वह आज के परिदृश्य में भी अत्यंत व्यावहारिक, वैज्ञानिक एवं लाभकारी है । खान पान हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है । वस्तुतः हमारे शरीर का निर्माण आहार से ही होता है तथा हानिकारक आहार रोगकारक होता है । अतः हमें स्वस्थ रहने के लिए भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए । उन्होंने बताया कि आहार ही हमारे शरीर का पोषण करता है । आजकल सही जानकारी के अभाव

में हम इसकी बहुत अनदेखी करते हैं । इसी कारण सितम्बर माह का पहला सप्ताह पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है । राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पोषण पर केंद्रित एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। भारत में, यह 1982 से हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इस दिन, विभिन्न स्थानीय और वैश्विक समुदाय विभिन्न आयोजनों और माध्यमों के माध्यम से पोषण के महत्व की वकालत करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस वर्ष, 2025, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का विषय है ' बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें ' । यह विषय स्वस्थ खान-पान की आदतों, संतुलित आहार और पोषण शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से छात्रों और परिवारों को लक्षित करके समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है और कुपोषण को रोकता है। आहार, विहार एवं आचार को स्वस्थ रहने का मूलमंत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि पोषण की दृष्टि से कहाँ, कब, कितना और कैसे खाया जाए यह जानना अत्यंत आवश्यक है । जहाँ निवास करते हैं उसके सौ किलोमीटर की परिधि में मिलने वाले अन्नपान ही हमारे लिए हितकर हैं । मिलेट्स के महत्व को बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि पेट सम्बन्धी रोगों के साथ-साथ अनेक जीवनशैली एवं अनूर्जता जन्य रोग हमारे इस पारम्परिक अनाज के सेवन से रोके जा सकते हैं । यह प्रसन्नता का विषय है कि आज विश्व आयुर्वेदीय औषधियों के साथ-साथ इसकी जीवनशैली की ओर आकृष्ट हो रहा है । अतः यह आवश्यक है कि हम महर्षियों की इस अमूल्य ज्ञान परम्परा को अपनी जीवनशैली का अंग बनाएँ । उन्होंने कहा कि आज चिकित्सा जगत को संक्रामक रोगों से नहीं जीवनशैली जन्य रोगों की अधिक चिंता है । आयुर्वेदीय जीवनशैली से इनका प्रभावी समाधान संभव है । डॉ तोमर ने ज़ोर देकर कहा कि आयुर्वेदीय जीवनशैली अपनाकर हम वर्तमान स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर सकते हैं । उन्होंने इस आयोजन के लिए आरोग्य भारती कानपुर प्रांत की सराहना की । इस कार्यक्रम का सफल आयोजन आरोग्य भारती के कानपुर प्रांत के सचिव श्याम सुंदर गुप्ता एवं योगाचार्य शशि गुप्ता ने किया । इस अवसर पर स्वस्थ ग्राम योजना प्रमुख डॉ रमाकांत पाण्डेय, प्रांत कार्यालय प्रमुख दिग्विजय सिंह एवं कानपुर उत्तर जिला संयोजक रवीन्द्र तिवारी सहित शताधिक कार्यकर्ताओं की प्रतिभागिता रही । कार्यक्रम का प्रारम्भ धन्वन्तरि वन्दना से हुआ एवं समापन शांति मंत्र के साथ सम्पन्न हुआ ।

हैदराबाद के भव्य गणेश विसर्जन में मुख्य अतिथि होंगे अमित शाह, देंगे बड़ा सियासी संदेश

हैदराबाद। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह 6 सितंबर को गणेश विसर्जन के एक विशाल समारोह को संबोधित करने हैदराबाद आएंगे। एएनआई से बात करते हुए, भाजपा तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अमित शाह 6 सितंबर को दोपहर 4 बजे हैदराबाद आ रहे हैं। वह गणेश विसर्जन के एक विशाल समारोह को संबोधित करेंगे, जो हैदराबाद में एक ऐतिहासिक आयोजन है... हर साल, लाखों लोग हुसैन सागर में इस जुलूस में भाग लेते हैं। लोग मोजमजही बाजार में इकट्ठा होंगे और वहीं से शोभा यात्रा शुरू होगी।

राव ने आगे बताया कि गणेश उत्सव समिति ने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गणेश उत्सव में अमित शाह को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। राव ने आगे कहा कि अमित शाह शोभा यात्रा देखेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा, राव ने नए जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए कहा, 'कई उत्पादों पर जीएसटी को 28 से घटाकर 18, 12 से घटाकर 5 और 5 से घटाकर 0 करने का फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत की बात है, किसानों, छात्रों, नागरिकों, परिवारों और देश के कई लोगों को इसका लाभ मिलेगा... मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया की सोच को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर पूरे तेलंगाना राज्य में प्रधानमंत्री मोदी का दुग्धाभिषेक किया जाएगा। 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को मिलाकर जीएसटी दरों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब में तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया। 5 प्रतिशत स्लैब में आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं, जिनमें खाद्य और रसोई के सामान जैसे मक्खन, घी, पनीर, डेयरी स्प्रेड, पहले से पैक नमकीन, भुजिया, मिश्रण और बर्तन; कृषि उपकरण जैसे ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर, जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, मिट्टी तैयार करने वाली मशीनें, कटाई के उपकरण, ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के टायर; हस्तशिल्प और लघु उद्योग जैसे सिलाई मशीन और उनके पुर्जे और स्वास्थ्य एवं कल्याण जैसे चिकित्सा उपकरण और डायग्नोस्टिक किट शामिल हैं।

बिहार में अब हर रविवार होगा 'हॉर्न फ्री', परिवहन विभाग ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए की अपील

पटना। राज्य में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने और शहरवासियों को शांत वातावरण मुहैया कराने के लिए परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। विभाग ने घोषणा की है कि अब से प्रत्येक रविवार को राज्य में हॉर्न फ्री दिन के रूप में मनाया जाएगा। इसके तहत वाहन चालकों और नागरिकों से अपील की गई कि वे रविवार को अनावश्यक हॉर्न न बजाए और यातायात नियमों का पालन करें। इस नियम का शिद्दत से पालन कराने के लिए कहा गया है। आम लोगों से इसका पालन करने की अपील की गई है।

विभाग के स्तर से जारी आदेश के अनुसार, अत्यधिक हॉर्न बजाने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जो लोगों को मानसिक अशांति के साथ नींद में खलल, तनाव, उच्च रक्तचाप जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। इस अभियान का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना, अनावश्यक हॉर्न बजाने की आदत को खत्म करना, शहर में शांत और स्वस्थय वातावरण के साथ सुरक्षित यातायात संस्कृति को स्थापित करना है।

कुकी-ज़ो एनएच-2 खोलने पर सहमत, हिंसाग्रस्त राज्य को राहत

इंफाल। कुकी-ज़ो परिषद ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मणिपुर में यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को खोलने का निर्णय लिया। यह कदम पिछले कुछ दिनों में गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकारियों और कुकी-ज़ो परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में हुई कई बैठकों के बाद उठाया गया है। इन चर्चाओं का उद्देश्य लंबे समय से जारी नाकेबंदी को दूर करना था, जिससे माल और वाहनों की आवाजाही बाधित हुई थी और राज्य भर के निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

एमएचए ने एक बयान में कहा कि कुकी-ज़ो परिषद ने एनएच-2 पर शांति बनाए

रखने के लिए भारत सरकार द्वारा तैनात सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। मणिपुर को नागालैंड और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण जीवनरेखा, एनएच-2 , मई 2023 में राज्य में भड़के जातीय तनाव के बीच अवरुद्ध हो गई थी। मुख्य रूप से मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच हुए इस संघर्ष के कारण व्यापक हिंसा, जान-माल की हानि, हज़ारों लोगों का विस्थापन और गहराता मानवीय संकट पैदा हुआ है।

राजमार्ग को फिर से खोलना एक विश्वास-निर्माण उपाय और हिंसा प्रभावित राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इंफाल और नई दिल्ली, दोनों जगहों के अधिकारियों का मानना ??है कि आवश्यक वस्तुओं की पहुँच आसान होने से विस्थापित परिवारों और राहत शिविरों में रह रहे नागरिकों की कठिनाइयों को कम करने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय ने आगे बताया कि इसके साथ ही, गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार, कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय बैठक भी हुई।

गृह मंत्रालय ने बताया कि बैठक का समापन एक त्रिपक्षीय संचालन निलंबन (एसओओ) समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुआ, जिसमें पुनः बातचीत की गई शर्तें (आधारभूत नियम) शामिल हैं, जो समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने कहा कि अन्य प्रावधानों के अलावा, संशोधित आधारभूत नियमों में दो प्रमुख बिंदुओं को दोहराया गया है, जिनमें 'मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता और मणिपुर में स्थायी शांति एवं स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता' शामिल है।

अफगानिस्तान में भूकंप का कहर, मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार, पीड़ितों के लिए भारत बना मसीहा

काबुल **(एजेंसी)**। अफगानिस्तान में गुरुवार सुबह फिर से भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसकी तीव्रता 4.8 रही और यह 135 किलोमीटर की गहराई में आया । इससे पहले बुधवार देर रात भी 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था। यह सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर था, इसलिए झटके ज्यादा खतरनाक साबित हुए। सतही भूकंप आमतौर पर ज्यादा नुकसान करते हैं क्योंकि इनके झटके सीधे सतह तक पहुंच जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, सतही (शैलो) भूकंप गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके झटके सतह तक तेजी से पहुँचते हैं और ज़्यादा तबाही मचाते हैं।

भूकंप में मरने वालों को आंकड़ा अब 2000 के पार हो चुका है लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ और ही बताए जा रहे हैं। इससे पहले कुनर प्रांत में पहले आए 6.0 तीव्रता वाले भूकंप में 1400 से अधिक लोग मारे गए व 3, 000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अधिकांश प्रभावित लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जहां मकान कच्ची ईंट और लकड़ी के बने थे।मृतकों और घायल लोगों की संख्या बढ़ने के बीच बचाव दल लगातार जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। प्रभावित इलाके में घर ढह गए हैं और सड़कें भूस्खलन के कारण बंद हो गई हैं, जिससे राहत कार्य में कठिनाई आ रही है।इसके कुछ समय बाद ही पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 5.2 मापी गई है। यह झटके उस भूकंप के ठीक बाद आए, जिसने रविवार रात को क्षेत्र को हिला दिया था और 1, 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई ।

भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावित कुनार और नंगरहार प्रांतों में हालात बेहद गंभीर हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने प्रभावित इलाकों में आपात राहत भेजी है। शुरुआती मदद में खाद्य सामग्री और हाई-एनर्जी बिस्किट भेजे गए हैं। जल्द ही और सहायता व कर्मियों को ले जाने वाली उड़ानें रवाना की जाएंगी। डब्ल्यूएफपी के क्षेत्रीय निदेशक हेरात्ड मानहार्ट ने हालात का वर्णन करते हुए कहा, 'घर मलबे में बदल गए हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, जगह-जगह भूस्खलन है और दुख की बात है कि कई जिंदगियां चली गईं।'उन्होंने बताया कि राहत टीमों के सामने टूटी सड़कें, दुर्गम इलाका और आफ्टरशॉक्स बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

भारत ने अफगानिस्तान को राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक्स पर जानकारी दी कि भारतीय सहायता काबुल पहुँच चुकी है। भारत की ओर से 21 टन राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें ब्लैंकेट, तंबू, हाइजीन किट, पानी स्टोरेज टैंक, जनरेटर, रसोई के बर्तन, पोर्टेबल वॉटर प्यूरीफायर, स्लीपिंग बैग, दवाइयाँ, व्हीलचेयर, सैनिटाइज़र, वाटर प्यूरीफिकेशन टैबलेट्स, ओआरएस और मेडिकल उपकरण शामिल हैं । जयशंकर ने लिखा- 'भारतीय भूकंप सहायता आज हवाई मार्ग से काबुल पहुँची। ज़रूरत की तमाम चीज़ें तुरंत भेजी गई हैं।' कुल मिलाकर, बार-बार आ रहे भूकंप और हालिया बाढ़ के कारण अफगानिस्तान का मानवीय संकट और गहरा गया है। राहत एजेंसियाँ और अंतरराष्ट्रीय मदद ज़मीन पर तेजी से काम कर रही हैं, लेकिन चुनौतियाँ अब भी बड़ी हैं।

वॉलमार्ट बना जंग का मैदान : पुलिस पर अचानक तेजधार हथियार से अटैक, लोगों में मची अफरा-तफरी

फ्लोरिडा। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के फोर्ट पीयर्स शहर में शनिवार रात एक वॉलमार्ट स्टोर के अंदर हुए माचेते (तेज़ धार वाले हथियार) हमले का बॉडीकैम फुटेज पुलिस ने जारी किया है। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया था। पुलिस द्वारा जारी वीडियो में दिखाई देता है कि किस तरह अधिकारी स्टोर के अंदर हमलावर का सामना कर रहे थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण था और हालात किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते थे। फोर्ट पीयर्स पुलिस विभाग ने बताया कि घायल अधिकारी की स्थिति अब स्थिर है और वह स्वस्थ होने की ओर हैं । इलाज की प्रक्रिया जारी है।हमले के बाद मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान स्टोर में मौजूद लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया।वॉलमार्ट में हुई इस घटना से खरीदारी कर रहे लोग काफी घबरा गए और अफरा-तफरी मच गई। कई लोगों ने हमलावर को माचेते लहराते देखा और तुरंत बाहर की ओर भागे।

बाढ़ग्रस्त पंजाब में ग्राउंड जीरो पर शिवराज किसानों का दर्द सुना, मदद का वादा

अमृतसर **(एजेंसी)**। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पंजाब के अमृतसर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आज अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने इलाके में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनीं। मंत्री चौहान ने लगातार भारी बारिश के कारण जलभराव से क्षतिग्रस्त फसलों का भी निरीक्षण किया और किसानों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री चौहान आज पंजाब के अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद चौहान देर शाम अमृतसर में अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए लौटेंगे।

शिवराज ने कहा कि आज पंजाब संकट में है। जलप्रलय की स्थिति है। फसलें डूबी हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। हम गांवों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे, ग्रामीणों से संवाद करेंगे। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब की जनता के साथ खड़ी है। बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, 'मैं कल (4 सितंबर) पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहा हूँ।

भारतीय-अमेरिकी अमित क्षत्रिय बने नासा के सह-प्रशासक, संभालेंगे चंद्रमा-मंगल मिशन की कमान

वाशिंगटन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय-अमेरिकी अमित क्षत्रिय को 'अन्वेषण-केंद्रित' नया सह-प्रशासक नियुक्त किया है। नासा में 20 साल सेवा दे चुके क्षत्रिय हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अन्वेषण प्रणाली विकास मिशन निदेशालय (ईएसडीएमडी) में चंद्रमा और मंगल से जुड़े अभियान कार्यक्रमों के उप-प्रभारी थे। नासा के एक बयान में कहा कि कार्यवाहक नासा प्रशासक सीन पी डफी ने बुधवार को अमित क्षत्रिय को नासा का अन्वेषण केंद्रित नया सह-प्रशासक नियुक्त किया।

विस्कॉन्सिन में भारतीय प्रवासी माता-पिता के घर जन्मे एवं कैलिफोर्निया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैलटेक) तथा ऑस्टिन स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त क्षत्रिय इतिहास में मिशन नियंत्रण उड़ान निदेशक के रूप में सेवा करने वाले लगभग 100 लोगों में से एक हैं। नासा की वेबसाइट पर उनके प्रोफाइल के अनुसार, वह 2003 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े थे। क्षत्रिय को अंतरिक्ष स्टेशन के 50वें अभियान के वास्ते प्रमुख उड़ान निदेशक के रूप में उनके कार्यों के लिए नासा उत्कृष्ट नेतृत्व पदक से सम्मानित किया गया था।

नासा ने कहा कि अपनी नयी भूमिका में वह एजेंसी में सर्वोच्च रैंक वाले सिविल सेवक के रूप में तथा डफी के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम करेंगे। कैलटेक के पूर्व छात्र के ब्लॉग के अनुसार, क्षत्रिय के पिता इंजीनियर थे और उनकी मां केमिस्ट थीं - दोनों ही भारतीय प्रवासी थे - जिन्होंने गणित और विज्ञान में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। क्षत्रिय और उनकी पत्नी के तीन बच्चे हैं।

मानवीय गरिमा संविधान की आत्मा : एक मंच पर नजर आए सीजेआई गवई और स्पीकर ओम बिरला

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी, कानूनी और कार्यकारी बाधाओं को दूर करने और सभी के लिए त्वरित न्याय और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए संस्थाओं में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने समय पर न्याय के माध्यम से मानवीय गरिमा की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सार्वजनिक संवाद और संवाद की तत्काल आवश्यकता पर भी बल दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई की उपस्थिति में एलएम सिंघवी स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए, लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक बाधाएँ न्याय में देरी का कारण बनी हुई हैं। उन्होंने नागरिकों और विचारकों से सभी के लिए शीघ्र और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने का आह्वान किया। इसके अलावा, ओम बिरला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बीआर अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने संविधान में मानवता, समानता, न्याय, सामाजिक-आर्थिक अधिकारों और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को गहराई से समाहित किया।

उन्होंने बताया कि संवैधानिक अनुच्छेदों और संविधान सभा की बहसों, दोनों में मानवीय गरिमा पर विशेष ज़ोर दिया गया है और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच सहयोगात्मक रूप से काम करने के महत्व पर ज़ोर दिया ताकि उनके कामकाज को बेहतर बनाया जा सके और सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान, मुख्य न्यायाधीश गवई ने भारतीय संवैधानिक कानून में मानवीय गरिमा के विकास का वर्णन किया और इसे संविधान की मूल भावना का आधार बनने वाला व्यापक सिद्धांत बताया।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने आगे बताया कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय ने गरिमा को लगातार एक मूल मूल्य के रूप में व्याख्यायित किया है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)